

# पूर्वी सिंहभूम में एक स्कूल के चारों तरफ भरा पानी, बचाए गए 162 छात्र

**PHOTON NEWS JAMSHEDPUR :** झारखंड में मानसून की लगातार हो रही बारिश से जगह-जगह तबाही जैसी स्थिति पैदा हो गई है। रविवार को भी राजधानी रांची सहित कई जिलों में झमाझम बारिश हुई। वहीं कई जिलों में रुक-रुककर बारिश होती रही। लगातार हो रही बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के कारण सड़कों से लेकर स्कूल तक में पानी भर गया है। रेस्क्यू करने के लिए प्रशासन को आना पड़ा। इस स्कूल में फंसे 162 छात्रों को बाहर निकाल लिया गया है। मामला पूर्वी सिंहभूम के कोवाली थाना क्षेत्र का है। शनिवार रात को यहां के हल्दीपोखर-कोवाली रोड पर स्थित पंडरसोली में एक स्कूल है। लगातार हो रही बारिश के कारण स्कूल चारों तरफ से पानी से घिर गया। पानी से घिर जाने के कारण बच्चे स्कूल में फंस गए। जब स्कूल डूबा तो विद्यालय प्रशासन में हड़कंप मच गया। स्कूल के अधिकारियों ने इसकी जानकारी प्रशासन को दी, तो प्रशासन ने बच्चों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और सभी बच्चों को बारी-बारी से बाहर निकाल लिया गया।

## विद्यालय प्रशासन में मच गया हड़कंप, एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया- नाव पर बैठाकर बाहर निकाले गए सभी बच्चे तबाही की स्थिति पैदा करने लगी लगातार हो रही झमाझम बारिश, सड़कों पर जल-जमाव, लोगों की बढ़ी परेशानी



अधिकतर जिलों में 2 जुलाई तक होगी बारिश

झारखंड के अधिकतर जिलों में दो जुलाई तक भारी बारिश होने की आशंका है। इसे लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार, जिन जिलों में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। इनमें 30 जून को राज्य के दक्षिणी-पूर्वी और इससे सटे मध्यवर्ती एवं उत्तरी भागों में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा पश्चिमी और उत्तरी मध्य भागों में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है।

### लातेहार में वर्षा का कहर : पुल गिरा, बाइक नदी में बही, दर्जनों गांवों का टूट संपर्क

लातेहार जिले में शनिवार शाम से शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने पूरे क्षेत्र में तबाही मचा दी है। तेज बारिश के चलते कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह टूट गया है। वहीं, बरवाडीह प्रखंड के कुटमू गांव में स्थित बड़का पुल टूट गया है। पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण दर्जनों गांवों का जिला और प्रखंड मुख्यालय से संपर्क कट गया है। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, यह इलाके का एकमात्र मुख्य पुल था और इसके टूटने से जामरा, पवही, सोहदाग, हेसलबा, माराबार समेत 12 से अधिक गांव टापू में तब्दील हो गए हैं।



### मुख्यमंत्री स्वयं स्थिति और व्यवस्था पर लगातार बनाए हुए हैं नजर

## भारी बारिश पर हाई अलर्ट, सीएम हेमंत ने की सतर्क रहने की अपील, स्कूल बंद करने का निर्देश

झारखंड में लगातार हो रही भारी बारिश और जल-जमाव से उत्पन्न बाढ़ जैसी स्थिति को देखते हुए राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी खुद लगातार व्यवस्था पर नजर रखे हुए हैं। इस बीच उन्होंने सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट किया है। इसमें लिखा है कि मौसम



विभाग द्वारा राज्य के जिलों में कुछ दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। आपदा प्रबंधन विभाग और सभी जिला

प्रशासन, मौसम विभाग एवं अन्य एजेंसियों के साथ निरंतर समन्वय स्थापित कर अलर्ट मोड पर रहते हुए आमजन को हर परिस्थिति में मदद पहुंचाने का कार्य करें। आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ. इरफान अंसारी लगातार हालात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सभी जिलों में राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।

SARAFA	
सोना	: 8,575
चांदी	: 108.00
(नोट : सोना 22 कैरेट प्रति ग्राम)	

### BRIEF NEWS

#### चारधाम यात्रा एक दिन के लिए स्थगित

**DEHRADUN :** उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के कारण पर्वतीय जनपदों में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। नदी-नाले उफान पर हैं। भारी वर्षा और भूस्खलन की आशंकाओं को देखते हुए चारधाम यात्रा को अगले 24 घंटे के लिए स्थगित किया गया है। यात्रियों और लोगों की सुरक्षा को लेकर संबंधित जिलों के प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है और राहत व बचाव दलों को सक्रिय किया गया है। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडेय ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्तमान मौसम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

#### बाहर नहीं भेजा जाएगा ब्लैक बॉक्स : मुरलीधर

**NEW DELHI :** अहमदाबाद में 12 जून को हुए एअर इंडिया विमान हादसे की जांच सभी पहलुओं से की जा रही है, जिसमें सांनिधि (संबोटाज) की संभावना को भी खंगाला जा रहा है। यह जानकारी केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोले ने दी है। उन्होंने कहा कि विमान दुर्घटना एएआईबी इस मामले की पूरी जांच कर रहा है। ब्लैक बॉक्स भारत में (एएआईबी के पास) है, उसे बाहर नहीं भेजा जाएगा। केंद्रीय मंत्री मोहोले पुणे ने कहा, 'यह दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था। एएआईबी इसकी हर एंगल से जांच कर रहा है।

#### कोरोना के नए वैरिएंट से एक महीने में 135 मौतें

**NEW DELHI :** देशभर में कोरोना वायरस के एक्टिव केसों की संख्या बीते 2 हफ्तों से कम हो रही है। बीते 24 घंटे में 30 नए केस सामने आए, जबकि 252 मरीज ठीक हुए हैं। एक्टिव केसों की संख्या घटकर 2086 पहुंच गई है। 12 जून को देशभर में 7131 एक्टिव केस थे। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, कोरोना के नए वैरिएंट से जनवरी 2025 से अब तक 142 की मौत हुई है। बीते दिन 3 लोगों ने जान गंवाई है, इनमें दिल्ली के 2 और हरियाणा का एक मरीज शामिल है। बीते एक महीने के करीब 135 मौतें हुई हैं। डॉ. नवीन कुमार कहा- सिंगापुर में फैल रहे निम्ब्स (एनबी.1.8.1) वैरिएंट के केस भारत में भी सामने आ रहे हैं।

## जगन्नाथ मंदिर से करीब 3 किमी दूर गुंडिचा मंदिर के सामने हुआ हादसा

# पुरी में जगन्नाथ रथयात्रा के बाद भगदड़, तीन लोगों की गई जान

BHUBANESWAR @ PTI :

रविवार को तड़के करीब 4 बजे ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथयात्रा के बाद भगदड़ मच गई। इसमें 3 लोगों की जान चली गई और 50 घायल हो गए। घायलों में 6 की हालत गंभीर है। हादसा जगन्नाथ मंदिर से करीब 3 किमी दूर गुंडिचा मंदिर के सामने हुआ। यहां भगवान जगन्नाथ के नंदीघोष रथ के दर्शन करने के लिए भारी भीड़ जुटी थी, इसी दौरान भगदड़ मची। हादसे में मारे गए लोगों के नाम बसंती साहू (36), प्रेमकांत महर्ति (78) और प्रभाती दास हैं। इनके शव पुरी मेडिकल कॉलेज में रखे गए हैं। सीएम मोहन चरण माझी ने घटना पर माफी मांगी है। उन्होंने 'एक्स' पर लिखा, मैं और मेरी सरकार भगवान जगन्नाथ के सभी भक्तों से व्यक्तिगत रूप से क्षमा मांगते हैं। यह लापरवाही

## 50 जखमी, घायलों में 6 की स्थिति गंभीर, सीएम मोहन चरण माझी ने मांगी माफी

### जगन्नाथ रथ बाद में पहुंचा दर्शन के लिए लगी होड़

नियमों के अनुसार, पुरी की रथयात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथों को उनकी मौसी के घर गुंडिचा मंदिर के सामने 9 दिन के लिए खड़ा कर दिया जाता है। यहां बलभद्र और सुभद्रा के रथ पहले पहुंच चुके थे। जगन्नाथ रथ बाद में पहुंचा, जिससे लोगों में उसके दर्शन करायी की होड़ लग गई। इसी दौरान भगदड़ मची, जिसमें गिरने से कई लोग कुचल गए। बताया जा रहा है कि घटना के समय वहां पर्याप्त पुलिस बल तैनात नहीं था।



### राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में मामला दर्ज

भगदड़ में तीन लोगों की मौत की घटना को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में मामला दर्ज किया गया है। मानवाधिकार कार्यकर्ता जयंत दास ने यह मामला दर्ज कराया है। मानवाधिकार कार्यकर्ता ने कहा है कि पुलिस डीजी और जिला

कलेक्टर को तुरंत हटाय़ा जाना चाहिए। इस मामले में पुलिस महानिदेशक वाई बी खुरानिया ने कहा है कि भगदड़ के पीछे के कारण का पता लगाने के लिए जांच जारी है। वहीं, खुरानिया ने घटना की जांच के निर्देश दिए।

माफ करने लायक नहीं है। इसके बाद राज्य सरकार ने पुरी के कलेक्टर और एसपी का तबादला कर दिया। चंचल राणा को नया कलेक्टर और पिनाक मिश्रा को नया एसपी बनाया गया है। साथ ही

## एसीबी की जांच में खुलासा : एजेंसी ने प्राथमिकी दर्ज करने की मांगी इजाजत हजारीबाग खासमहल घोटाले में होगी एफआईआर

**PHOTON NEWS RANCHI :** हजारीबाग जिले में खासमहल भूमि से जुड़ा एक बड़ा घोटाला सामने आया है। इस मामले में एसीबी की जांच में चौकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। मामले में तत्कालीन हजारीबाग डीसी विनय कुमार चौबे सहित कई अधिकारियों और निजी व्यक्तियों पर खासमहल और ट्रस्ट को आवंटित भूमि का अवैध हस्तांतरण कराने का आरोप है। इस घोटाले को लेकर एसीबी ने 2015 में एक प्रीलिमिनरी इन्क्वायरी (पीई) दर्ज की थी। जांच में यह सिद्ध हुआ कि, हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना की गई। दाखिल खारिज में 'सेवायत' शब्द हटाकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बंदोबस्त की गई। अधिकारियों की मिलीभगत से करोड़ों रुपये की सरकारी संपत्ति निजी व्यक्तियों के हाथों में पहुंचाई गई। एसीबी ने अब इस घोटाले में नामजद अधिकारियों और लाभार्थियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने की संसुति के साथ फाइल राज्य सरकार को भेज दी है।

## तत्कालीन डीसी विनय चौबे सहित कई अधिकारियों पर है आरोप



खासमहल व ट्रस्ट को आवंटित 2.75 एकड़ भूमि के अवैध हस्तांतरण से जुड़ा है मामला

2015 में दर्ज हुई थी पीई, जांच में हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना की बात आई सामने

### 23 लोगों को आवंटित की गई भूमि

यह मामला हजारीबाग की 2.75 एकड़ खासमहल भूमि से संबंधित है, जिसे 1948 में 30 वर्षों के लिए एक ट्रस्ट सेवायत को लीज पर दिया गया था। यह लीज 1978 में समाप्त हो गई थी और 2008 तक इसका नवीकरण किया गया। 2008 से 2010 के बीच एक सुनियोजित प्रशासनिक षड़यंत्र के तहत इस भूमि को सरकारी भूमि घोषित कर 23 निजी व्यक्तियों को आवंटित कर

दिया गया। आरोप है कि इस षड़यंत्र के केंद्र में तत्कालीन हजारीबाग विनय कुमार चौबे थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने खासमहल पदाधिकारी के साथ मिलकर लीज नवीनीकरण के लिए दिए गए आवेदन से सेवायत शब्द जान-बूझकर हटवाया। ऐसा इसलिए किया गया, ताकि ट्रस्ट भूमि को सरकारी दिखाया जा सके और उसका अवैध रूप से हस्तांतरण संभव हो सके।



## रूसी हमले में यूक्रेन का एफ-16 हुआ तबाह पायलट की गई जान

**NEW DELHI :** रूस ने रविवार की रात को यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया। रूस ने 477 ड्रोन और 60 मिसाइलों समेत 537 हवाई हमले किए। रूस ने यूक्रेन पर एम/केएन-28 बैलिस्टिक मिसाइल, 33 केएन-101/इस्केंडर-के क्रूज मिसाइल और 4 फेलिब्र क्रूज मिसाइलें भी दागीं। यूक्रेन डिफेंस मिनिस्ट्री ने सोशल मीडिया पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। यूक्रेनी वायु सेना ने इनमें से 475 हमलों को रोक दिया गया। हालांकि इस दौरान यूक्रेन के एफ-16 पायलट पावेलो इवानोव की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रूसी हमले को जवाब देते वक्त एक मिसाइल ने पावेलो के एफ-16 को हिट किया था। रूसी हमलों में रविवार को यूक्रेन के एक पायलट की मौत हो गई और एक एफ-16 लड़ाकू विमान तबाह हो गया। हमलों में घरों और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा और छह लोग घायल हो गए। यूक्रेनी वायु सेना ने कहा कि पायलट ने रूस के मिसाइल हमले के दौरान सात मिसाइलों को मार गिराया, लेकिन अंतिम लक्ष्य को मार गिराते समय उसका विमान खराब हो गया था।

## न्यू स्टडी पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में अधिक प्रभाव डाल रहा जलवायु परिवर्तन

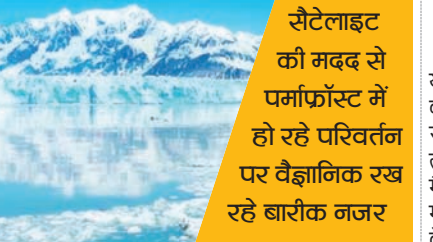
# तापमान बढ़ने से पिघलने लगी आर्कटिक धरती की बर्फीली मिट्टी

PHOTON NEWS • RESEARCH DESK :

सौरमंडल में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है, जहां प्रकृति और जीवन की निरंतरता है। उत्तरी ध्रुव पृथ्वी का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहां पृथ्वी का पूर्ण अंश इसकी सतह को काटता है। यह आर्कटिक महासागर के बीच में स्थित है, जो अत्यधिक ठंडा होता है। यहां छह महीने का दिन और छह महीने की रात होती है। उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला भौगोलिक क्षेत्र आर्कटिक क्षेत्र कहलाता है। इसे ही आर्कटिक धरती भी कहते हैं। यह आर्कटिक वृत्त के भीतर स्थित है, जो भूमध्य रेखा के उत्तर में लगभग 66.5 डिग्री अक्षांश पर एक काल्पनिक रेखा है। इस क्षेत्र में आसपास के द्वीप, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के कुछ हिस्से शामिल हैं। आर्कटिक क्षेत्र में कठोर जलवायु होती है, जिसमें लंबी, ठंडी सर्दियां और छोटी, ठंडी ग्रीष्मकाल होती है। आर्कटिक महासागर का एक बड़ा हिस्सा पूरे वर्ष बर्फ से ढका रहता है, जिसे समुद्री बर्फ कहा जाता है। हाल के विशेष अध्ययन से यह जानकारी सामने आई है कि आर्कटिक धरती का तापमान सबसे तेजी से बढ़ रहा है।

## आर्कटिक महासागर के बीच स्थित इस हिस्से में पूरे वर्ष जमी रहती है बर्फ इस क्षेत्र में आसपास के द्वीप, उत्तरी अमेरिका, यूरोप व एशिया के कुछ भाग शामिल

- शेष दुनिया की अपेक्षा इस क्षेत्र में चौगुनी तेज गति से बढ़ रही गर्मी
- मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के मौसम वैज्ञानिकों ने लंबे समय तक किया विशेष अध्ययन
- हजारों वर्षों से जमी बाफीली मिट्टी (पर्माफ्रॉस्ट) पिघलने से वायुमंडल में जा रहा ज्यादा कार्बन



सेटेलाइट की मदद से पर्माफ्रॉस्ट में हो रहे परिवर्तन पर वैज्ञानिक रख रहे बारीक नजर

वर्षों तक वातावरण में घुलता रहेगा कार्बन वैज्ञानिकों का कहना है कि पर्माफ्रॉस्ट पिघलने से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक बार जब यह मिट्टी पूरी तरह पिघलनी शुरू हो जाती है, तो उसमें मौजूद

जैविक कार्बन धीरे-धीरे वर्षों तक वातावरण में घुलता रहता है। इसलिए वैज्ञानिक अब इस बात पर विशेष ध्यान दे रहे हैं कि पर्माफ्रॉस्ट की भूमिका को अच्छे से समझा जाए।

## गलने लगे हैं जैविक पदार्थ

यह प्रक्रिया मिट्टी में मौजूद कार्बन को वायुमंडल में पहुंचा रही है, जिससे धरती का तापमान और बढ़ रहा है। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर मीटोरोलॉजी के शोधकर्ताओं के अनुसार, पर्माफ्रॉस्ट वह मिट्टी होती है, जो हजारों वर्षों से लगातार जमी हुई है। इसमें बड़ी मात्रा में जैविक पदार्थ दबे हैं। ये जैविक पदार्थ जब तापमान बढ़ने से गलने लगते हैं, तो वे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसों के रूप में वातावरण में मिल जाते हैं। ये गैसें पृथ्वी को गर्म करने वाली सबसे घातक गैसों में से हैं। यह प्रक्रिया अब एक निर्णायक बिंदु यानी ऐसा मोड़ ले सकती है, जिसके बाद इस प्रक्रिया को रोकना नहीं जा सकेगा। यह जलवायु तंत्र के लिए एक ऐसी अवस्था है जो यदि एक सीमा के पार चली गई, तो फिर इसे पहले जैसा लौटाना संभव नहीं होगा, भले ही वैश्विक तापमान में गिरावट आने लगे।

## आपातकाल संविधान की हत्या, न्यायपालिका को गुलाम बनाने का प्रयास



**NEW DELHI @ PTI :** रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के 123वें एपिसोड में अनेक विषयों पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने हाल के दिनों में देश में हुए सकारात्मक बदलावों, सांस्कृतिक पर्वों, सामाजिक सहभागिता, महिलाओं की प्रगति, पर्यावरण संरक्षण और भारत की अंतरराष्ट्रीय उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए देशवासियों को गर्व और प्रेरणा का अनुभव कराया। मोदी ने आपातकाल की 50वीं बरसी पर उसके काले अध्याय को याद किया और कहा कि यह सिर्फ संविधान की हत्या नहीं थी, बल्कि न्यायपालिका को भी गुलाम बनाने का प्रयास किया गया था। उन्होंने उन हजारों लोगों को श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने अत्याचारों का सामना करते हुए लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1975 में लगाए गए आपातकाल

कार्यक्रम के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, बाबू जगजीवन राम व अटल बिहारी वाजपेयी के पुराने ऑडियो भी किए साझा

विद्यार्थियों को भी किया गया परेशान, अभिव्यक्ति की आजादी का घोट दिया मला

## संविधान को सशक्त बनाने की प्रेरणा

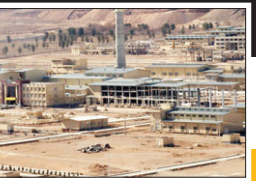
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आखिरकार, जनता-जनार्दन की जीत हुई। आपातकाल हटा लिया गया और आपातकाल थोपने वाले हार गए। मोदी ने कहा, यह भारत की जनता का सामर्थ्य था कि वो झुकी नहीं, टूटी नहीं और लोकतंत्र के साथ कोई समझौता स्वीकार नहीं किया। अंततः आपातकाल लगाने वालों की हार हुई। मोदी ने कहा कि देश पर आपातकाल थोपे जाने के 50 वर्षों के बाद ही

पुरे हुए हैं। हम देशवासियों ने संविधान हत्या दिवस मनाया है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की भव्यता का वर्णन करते हुए बताया कि इस बार योग दिवस पर तीन लाख लोगों ने विशाखापत्तनम के समुद्र तट पर एक साथ योग किया। दो हजार से अधिक आदिवासी छात्रों ने 108 मिनट तक सूर्य नमस्कार किए। दिल्ली में यमुना के किनारे योग को स्वच्छता के संकल्प से जोड़ा गया।

## आईईएई डायरेक्टर राफेल ने दी जानकारी ईरान के पास न्यूक्लियर बम बनाने के लिए यूरेनियम मौजूद

AGENCY NEW DELHI :

रविवार को यूएन की इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी (आईएएन) ने कहा कि ईरान कुछ महीनों में अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से शुरू कर सकता है। आईएएन डायरेक्टर राफेल ग्रॉसी ने एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि ईरान की कुछ न्यूक्लियर फैसिलिटी अभी भी बची हुई हैं। ग्रॉसी ने कहा- ईरान के पास 60% थ्योर यूरेनियम का भंडार है, जो एटम बम बनाने के लिए काफी है। इस भंडार को अमेरिकी हमले से पहले हटा दिया गया था या फिर ये तबाह हो गया, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। इजरायल ने 13 जून को ईरान



ईरान के पास 60% थ्योर यूरेनियम का भंडार, जो एटम बम बनाने के लिए काफी

के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमले शुरू किए हैं। बाद में अमेरिकी ने बी-2 बॉम्बर से हमला कर ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करने का दावा किया था।



# जमीन के 4 फीट नीचे दबा था बच्चे का शव, पत्थर हटाते ही सन्न रह गए लोग

## शव की पहचान करने में जुटी पुलिस, थानों से जुटाई जा रही गुमशुदगी की रिपोर्ट

**PHOTON NEWS GIRIDIH :** गिरिडीह जिले के नवडीहा ओपी क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दलागी पुल के नीचे जमीन के चार फीट अंदर एक सात साल के बच्चे का शव मिला है। शव पर पत्थर रखे हुए थे, जिससे यह आशंका गहरा गई है कि यह हत्या का मामला हो सकता है।

रविवार सुबह कुछ ग्रामीण शौच के लिए नदी किनारे गए थे। इसी दौरान उन्होंने देखा कि पुल के नीचे पत्थरों के पास कई कुत्ते मंडरा रहे हैं और वहां से सड़ांध आ रही थी। जब स्थानीय लोगों ने इस बात की सूचना नवडीहा ओपी पुलिस को दी, तो प्रभारी दीपक कुमार और जमुआ थाना प्रभारी मणिकांत कुमार फौरन टीम के



पुल के नीचे व ऊपर जुटी लोगों की गीड़

● फोटोन न्यूज

साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से खोदाई की गई, जिसमें करीब चार फीट नीचे से बच्चे का शव बरामद किया गया। शव निकालते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।

पुलिस के अनुसार, अब तक शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। मृत बच्चे की उम्र लगभग 7 वर्ष होगी। एसडीपीओ खोरीमहुआ राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि यह पता लगाया जा रहा है कि यह बच्चा किसके

घर का था और किन हालात में जमीन में दफनाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगा कि मौत सामान्य थी या हत्या। पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है।

### BRIEF NEWS

#### ब्लू स्टोन की तस्करी में एक गिरफ्तार

**KODERMA :** कोडरमा थाना के गिरिडीह रोड स्थित क्षत्रिय धर्मशाला के पास एक घर से 15 किलो कीमती ब्लू स्टोन और दो वाहन जब्त किए गये हैं। पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना पर यह कार्रवाई की गयी है। पुलिस को सूचना थी कि राजीव सिंह उर्फ ललन सिंह ने अपने घर में सहयोगी के साथ मिलकर लोकाई के जंगल क्षेत्र से उत्खनित ब्लू स्टोन को राजस्थान भेजने का योजना बना रहा है। पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी विकास कुमार पासवान के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने क्षत्रिय धर्मशाला के समीप राजीव सिंह उर्फ ललन सिंह के घर पर छापेमारी कर एक आरोपित बंटी कुमार रजक (25) को गिरफ्तार किया। साथ ही ललन सिंह के घर में रखे करीब 15 किलो ग्राम ब्लू स्टोन, क्रेटा वाहन (आरजे 45सीआर 2151 ) एवं होण्डा कार (जेएच 07एच0050 ) की जांच करने पर दो डायरी, एक कॉपी एवं दो मोबाइल को जब्त किया। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ करने पर पता चला कि लोकाई गांव के प्रतिबंधित जंगल क्षेत्र से उत्खनित अवैध ब्लू स्टोन के खरीद-बिक्री के संबंध में ललन सिंह और अन्य सहयोगी के साथ अपने घर में इकट्ठा हुए थे। पुलिस को आता देख सभी अंधेरा का लाभ उठाकर वहां से फरार हो गए। बंटी कुमार ने बताया कि ललन सिंह उर्फ राजीव सिंह और सिकन्दर दास बरसोतियाबर के नेतृत्व में सभी लोगों के जरिये अवैध उत्खनन कर ब्लू स्टोन को खरीद कर वाहनों से राजस्थान में ले जाकर व्यापार किया जाता है।

#### हजारीबाग के सांसद बुजुर्गों को करा रहे तीर्थयात्रा

**HAZARIBAG :** हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने सेवा, विकास और संस्कृति के समन्वय को सार्थक रूप देते हुए सांसद तीर्थ दर्शन महाअभियान की शुरूआत की है। इस अभियान की पहली आध्यात्मिक यात्रा रविवार को कटकमदग प्रखंड के खपरियावां स्थित भगवान नृसिंह मंदिर से प्रारंभ हुई। इस भावनात्मक और भव्य अवसर पर सैकड़ों की संख्या में लोग जुटे और श्रद्धालु बुजुर्गों की विदाई समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम के तहत खपरियावां और नवादा पंचायत के तीन गांवों से चयनित कुल 180 बुजुर्ग श्रद्धालु वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज और विन्ध्यवासिनी की धार्मिक यात्रा पर रवाना हुए। तीर्थयात्रियों को विदा करने से पूर्व भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह और सांसद मनीष जायसवाल ने स्वयं उनके चरण पखावर आशीर्वाद लिया।

#### करंट लगने से युवक की मौत

**CHAIBASA :** पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर प्रखंड अंतर्गत पुशालोटा गांव में घर में लाइट जलाते समय 25 वर्षीय युवक की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान सौरभ हेंड्रम के रूप में हुई है। घटना उस समय हुई जब घर में पूरा परिवार मौजूद था। सौरभ बिजली बोर्ड से बल्ब जलाने के लिए प्लक ऑन कर रहा था, लेकिन अचानक पूरे बोर्ड में करंट दौड़ गई। बोर्ड को छूते ही करंट लग गया। परिजन तुरंत उसे अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सौरभ अपने परिवार का पालन-पोषण करने वाला मुख्य सदस्य था।

## खूटी में ग्राम प्रधान की हत्या, घर में घुस कर अपराधियों ने पीटने के बाद मारी गोली

**PHOTON NEWS KHUNTI :** खूटी जिले के लांघु पंचायत अंतर्गत काड़ेतुबिद गांव में शनिवार को देर रात ग्राम प्रधान बलराम मुंडा की हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि उनके घर में घुसकर दर्जनों हथियारबंद अपराधियों ने लाठी-डंडों से पिटाई करने के बाद गोली मार दी। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। घटना के समय तेज बारिश हो रही थी और ग्राम प्रधान बलराम मुंडा अपने घर में मौजूद थे। इसी दौरान दर्जनों अपराधी घर में जबरन घुस गए और उन्हें निशाना बनाया। पहले लाठी-डंडों से पीटा गया और फिर गोली मार दी गई। मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। बलराम मुंडा को पिटा देख उनका भांजा आचू मुंडा उन्हें बचाने दौड़ा, लेकिन अपराधियों ने उस पर भी जानलेवा हमला

**जांच में जुटी पुलिस 10 संदिग्ध हिरासत में** घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। डीएसपी वरुण रजक ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि हत्या गंभीर प्रकृति की है और इसकी हर पहलू से जांच की जा रही है। पुलिस ने देर रात ही सड़कों पर चेकिंग अभियान चलाया और अब तक 10 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। प्रारंभिक जांच में यह मामला ठेकेदारी से जुड़े विवाद से भी जुड़ा बताया जा रहा है।

किया। वह गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है।

स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, अपराधी लगभग आधे घंटे तक घर में रहे। इस दौरान उन्होंने घर में रखे धान के बोरे फाड़ दिए और अन्य कीमती सामानों को

भी क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना को डकैती के इरादे से अंजाम दिया गया बताया जा रहा है।

**परिजनों ने लगाया डकैती का आरोप**

परिजनों ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि देर रात अपराधी डकैती की नीयत से घर में घुसे थे। जब बलराम मुंडा ने इसका विरोध किया, तो उन पर हमला कर दिया गया। पुलिस इस हत्याकांड की हर एंगल से जांच कर रही है।

**जांच जारी, जल्द होगा खुलासा**

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, फिलहाल 10 लोगों से पूछताछ की जा रही है और कुछ महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूरे हत्याकांड का खुलासा किया जाएगा।

**PHOTON NEWS DHANBAD :** धनबाद जिले के रामकनाली ओपी क्षेत्र में बीसीसीएल (भारत कोकिंग कोल लिमिटेड) की आउटसोर्सिंग परियोजना के खिलाफ ग्रामीणों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें महिलाओं समेत दर्जनों ग्रामीण घायल हो गए। यह घटना कतरास क्षेत्र में संचालित मां अंबे माइनिंग आउटसोर्सिंग परियोजना के बुद्ध बाबू बांग्ला पैच के पास घटी, जहां कुम्हार बस्ती के ग्रामीण होलपैक सड़क निर्माण का विरोध कर रहे थे। कुम्हार बस्ती के निवासी, जो परंपरागत रूप से मिट्टी के बर्तन और मूर्तियां बनाकर जीवन यापन करते हैं, बीसीसीएल की सड़क निर्माण परियोजना को अपने जीवन पर संकट मान रहे हैं। ग्रामीणों का



घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस के जवान

● फोटोन न्यूज

#### मोबाइल से फोटो खींचने पर बढ़ा बवाल

घटना की सूचना मिलने पर कतरास, राजगंज, तेलुमारी, रामकनाली और अंगारपथरा ओपी की पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन वे हटने को तैयार नहीं थे। इसी बीच मोबाइल से फोटो खींचने पर एक युवक को रोका गया, जिससे मामला और भड़क गया। स्थिति बेकाबू होते ही पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें भवानी देवी, अंजुली कुमारी, गीत देवी, संजु देवी, सोनू कुमार समेत कई ग्रामीण घायल हो गए। दो पुलिसकर्मियों के भी घायल होने की सूचना है।

#### भाकपा-माले का विरोध

घटना की जानकारी मिलते ही भाकपा-माले नेता हलधर महतो और ठाकुर महतो मौके पर पहुंचे और प्रबंधन पर ग्रामीणों के साथ बर्बरता का आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि विस्थापन का समाधान नहीं किया गया तो यह मामला लोकसभा और विधानसभा में उठाया जाएगा।

कहना है कि उनके पुनर्वास की कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई है और प्रबंधन मिट्टी को काटकर



घटनास्थल पर जुटे लोग

● फोटोन न्यूज

## कोडरमा में गजराज का आतंक एक को कुचल कर मार डाला

**KODERMA :** कोडरमा जिले में हाथियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। बीते दो महीनों में चार लोगों की जान जा चुकी है, जबकि किसानों की फसलें और घरों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। ताजा घटना जयनगर थाना क्षेत्र के पिसपीरो गांव की है, जहां रविवार सुबह 55 वर्षीय रविंद्र यादव उर्फ नन्हकू यादव को हाथी ने मार डाला। ग्रामीणों के अनुसार रविंद्र यादव सुबह गांव के अन्य लोगों के साथ शौच के लिए रेलवे ट्रैक के किनारे गए थे। तभी यदुडीह हॉल्ट के पास उन्हें एक हाथी ने घेर लिया। जब तक वे वहां से भाग पाते, हाथी ने उन्हें सूई से पटककर पैरों से कुचल दिया। आसपास के ग्रामीणों ने शोर मचाकर झुंड को भगाया, लेकिन तब तक नन्हकू यादव की मौत हो चुकी थी। इससे पूर्व भी जयनगर और मरकच्यो थाना क्षेत्र में तीन अन्य लोग हाथियों के हमले में मारे जा चुके हैं। हाथियों का झुंड इन इलाकों में लगातार घूम रहा है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। घटना के बाद ग्रामीणों ने शव के साथ गांव में धरना दे दिया और वन विभाग से उचित मुआवजे की मांग की। वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी रविंद्र कुमार और जयनगर पुलिस मौके पर पहुंचे। रंजर रविंद्र कुमार ने बताया कि मृतक के परिजनों को तत्काल 25,000 रुपये की सहायता राशि दी गई है। कुल 4 लाख रुपये मुआवजे का प्रावधान है, शेष राशि कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद दी जाएगी।

## चतरा में लाखों के ब्राउन शुगर के साथ दो तस्क़र किए गए गिरफ्तार

### गिद्धौर में फुटबॉल मैदान के पास से जब्त किए गए 286 ग्राम मादक पदार्थ

#### ● गुप्त सूचना पर एसडीपीओ के नेतृत्व में की गई थी छापेमारी

**AGENCY CHATRA :** प्रतिबंधित अफीम और ब्राउन शुगर तस्क़रों के विरुद्ध चतरा पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है। रविवार को गिद्धौर में पुलिस ने लाखों के ब्राउन शुगर के साथ दो तस्क़रों को गिरफ्तार की है। पुलिस ने 286 ग्राम ब्राउन शुगर, इलेक्ट्रॉनिक माप तोल मशीन और विभिन्न कंपनियों का पांच मोबाइल फोन जब्त किया है। पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार अग्रवाल ने समाहरणालय स्थित कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर



पत्रकारों को जानकारी देते पुलिस पदाधिकारी

● फोटोन न्यूज

बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर सिमरिया एसडीपीओ शुभम खंडेलवाल के नेतृत्व में गठित गिद्धौर पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए गिद्धौर फुटबॉल मैदान

के समीप से अभियान चलाकर दोनों तस्क़रों गिद्धौर तेली टोला निवासी अभिमन्यु कुमार साव और प्रतापपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जोगियारा के नौकाडीह गांव

निवासी नितेश कुमार उर्फ त्रिवेणी उर्फ वेणी को गिरफ्तार किया है। उनके पास से लगभग 60 लाख रुपए की प्रतिबंधित ब्राउन शुगर की बरामदगी हुई है। उन्होंने कहा कि अफीम और ब्राउन शुगर की तस्क़री की सूचना पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। गुप्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सिमरिया एसडीपीओ शुभम कुमार खंडेलवाल के नेतृत्व में गिद्धौर थाना प्रभारी कुमार गौतम और सशस्त्र बल के जवानों की टीम बनाकर अभियान चलाया गया। एसपी ने बताया कि इसी क्रम में तस्क़र पकड़े गये। एक तस्क़र भगने में सफल रहा। उसकी पहचान कर ली गई है। वह जल्द पकड़ा जायेगा।

## मजदूर की पिटाई करने वाला पुलिस का जवान हुआ सस्पेंड

**CHATRA :** शहर के गंदौरी मंदिर के समीप एक होटल के बाहर पुलिस के जवान और मजदूर के बीच मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया में रविवार को वायरल हुआ है। सिविल ड्रेस में एक जवान एक मजदूर के साथ मारपीट कर रहा था। होटल के बाहर बाइक पार्किंग के दौरान बहस के बीच मारपीट हुई थी। यह घटना शनिवार शाम की थी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद चतरा एसपी सुमित कुमार अग्रवाल ने संज्ञान लिया और आरोपित जवान को सस्पेंड कर दिया है। सदर थाना में तैनात जैप का जवान मनीष कुमार सिविल ड्रेस में था। आसपास के लोगों ने बीच बचाव भी किया इसके वाक्यजुद उसने मारपीट की थी। जैप



वायरल वीडियो का फुटेज

जवान मनीष अपने साथी अंकित कुमार के साथ बुलेट से यहां आया था। एक मजदूर बुलेट के पीछे अपनी बाइक लगा दी थी। जिसके बाद मारपीट हुई। इस बारे में चतरा एसपी ने कहा कि सदर थाना प्रभारी को जांच करने का निर्देश दिया है। पुलिस जवान की आम जनता के प्रति अमर्यादित व्यवहार को देखते हुए उसे सस्पेंड कर दिया गया है।







**JAMSHEDPUR :** तुलसी भवन द्वारा आयोजित तुलसी जयंती समारोह के अंतर्गत कक्षा 8 से 12 तक के छात्रों के लिए रविवार को विषय संप्रेषण (भाषण) प्रतियोगिता हुई। इसमें नगर के 23 विद्यार्थियों के 86 विद्यार्थियों ने संत तुलसीदास के व्यक्तित्व व कृतित्व पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम के आरंभ में संस्थान के मानद मेसर्सचिप डॉ. प्रसेनजित तिवारी ने उद्घाटन लेमों का स्वागत करते हुए पुरे कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी दी। प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका डॉ. यमुना तिवारी ब्यथि, डॉ. अरुण सज्जन, विजयाशक्ती 'वेल्स', डॉ. उदय प्रताप हाथि, दिनेश्वर पिपाटी, अनिता निधति, नीलिमा पांडेय, डॉ. वीणा पांडेय 'भारती', कैलाश नाथ शर्मा 'गणजीपुरी' व राजेश राहें। छात्रों को प्रतिभागिता प्रमाणपत्र एवं उपहार प्रदान करने वालों में सुभाषचंद्र मुलार्का, रामचंद्रन प्रसाद, डॉ. प्रसेनजित तिवारी आदि रहे।



उन्होंने आपातकाल को याद किया। तत्पश्चात् संविधान रक्षकों को नमन करते हुए पवित्र यात्राओं द्वारा की जाने वाली सफाई प्रयासों, स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं की सफलता व प्रकृति संरक्षण के महत्व सहित कई दिलचस्प विषयों पर जानकारी साझा की। पीएम ने वितयनाम में पूज्यनीय भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों पर बात की तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत को गम्भीर बीमारी ट्रेकोमा मुक्त होने की जानकारी के साथसाथ देश के 95 करोड़ लोग सरकारी योजनाओं के लाभार्थी होने पर कहा कि उन्हें आने वाले दिनों में देश और सशक्त होना।



## आतंक के विरुद्ध भारत की दृढ़ता, नहीं की जा सकती आतंकी हमलों की अनदेखी

चीन के किंगदाओ शहर में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन आतंक के खिलाफ भारत की दृढ़ता के लिए याद किया जाएगा। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एससीओ के उस संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, जिसमें पहलगां आतंकी हमला के उल्लेख तो नहीं था, उलटे बलूचिस्तान का संदर्भ जोड़ दिया गया था। भारत का यह रुख पहलगाम आतंकी हमले के बाद से कायम उसके रवैए के अनुरूप ही है कि आतंक के साथ अब कोई समझौता नहीं किया जाएगा और अगर भारत किसी मंच पर इसे अलग-थलग भी पड़ जाए तो उसे उसकी कोई परवाह नहीं। इससे पहले आपरेशन सिंदूर के बाद भी विभिन्न देशों में भेजे गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों के माध्यम से भी भारत ने वैश्विक समुदाय को पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को बेनकाब करने का जोरदार अभियान चलाया था। एससीओ के मंच पर भी भारत ने उसी नीति की निरंतरता को प्रदर्शित किया। मूल रूप से चीन के वर्चस्व वाले एससीओ का भारत काफी समय बाद सदस्य बना है। पाकिस्तान भी इसका सदस्य है। इस समूह के प्रमुख उद्देश्यों में से एक यह भी है कि आतंकवाद और चरमपंथ के खिलाफ वह क्षेत्रीय सहयोग के लिए आधार तैयार करने की भूमिका निभाएगा, लेकिन इसकी कार्यप्रणाली उसके चरित्र से मेल नहीं खाती। समय के साथ इस संगठन में चीन का वर्चस्व और बढ़ता गया है। इसका एक कारण बदले हुए वैश्विक समीकरणों में रूस पर लगे तामाम प्रतिबंध भी हैं, जिनके चलते मास्को की बीजिंग पर निर्भरता बढ़ी है। अन्यथा रूस भी इस समूह में एक संतुलक की भूमिका निभाता रहा है। बढ़ते दबदबे का लाभ चीन अपने निहित स्वार्थों को साधने में कर रहा है। पाकिस्तान का पुरजोर समर्थन इसकी पुष्टि करता है। यह किसी से छिपा नहीं है कि आतंकवाद को लेकर चीन कई मौकों पर पाकिस्तान की ढाल बना है और ऐसा ही एक प्रयास उसने एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भी किया। यह इससे स्पष्ट झलकता है कि पहलगाम के जिस आतंकी हमले की दुनिया भर में कड़ी भर्त्सना हुई उसका उल्लेख तक एससीओ दस्तावेज में नहीं किया गया। उलटे उस बलूचिस्तान का प्रसंग जोड़ा गया, जहां पाकिस्तानी सेना द्वारा स्थानीय लोगों का बर्बरता से किया जा रहा दमन मानवीय उपीड़न के नए रिकार्ड बना रहा है। पहलगाम का संदर्भ हटाकर और बलूचिस्तान का मुद्दा जोड़ने की यह कवायद भारत को असहज करने के लिए ही की गई और ऐसी स्थिति में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर से किनारा करके बिल्कुल सही किया। असहमति के इस संदेश की गुंज दुनिया भर में सुनी जाएगी। चीन और पाकिस्तान को लेकर अक्सर कहा जाता है कि भारत को दो मोर्चों पर लड़ाई के लिए अपनी तैयारी करनी होगी, लेकिन देखा जाए तो यह दोहरा नहीं, बल्कि एक ही मोर्चा है। हम चीन और पाकिस्तान को अलग करके नहीं देख सकते। चीन का पाकिस्तान प्रेम इस कदर बढ़ चुका है कि उसके लिए वह कोई भी कदम उठाने को तैयार दिखता है। एससीओ के हालिया सम्मेलन की ही बात करें तो किसी भी संगठन में चेंबर या प्रमुख की भूमिका वाले देश का एक दायित्व यह भी होता है कि वह समूह के समक्ष आए एजेंडे पर सहमति बनाए। यदि सहमति न भी बना पाए तो ऐसा करने के लिए प्रयासरत तो दिखना चाहिए, लेकिन रक्षा मंत्रियों की बैठक से जुड़े संयुक्त बयान के मामले में चीन ने ऐसी कोई कोशिश तक नहीं की। दोनों देशों की यह मिलीभगत वह दुराभिसंधि दर्शाती है, जिसका भारत को समय रहते कोई तोड़ खोजना होगा। पाकिस्तान के साथ निपटना भारत के लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसे मिलता चीन का साथ इस चुनौती को और विकराल बनाता जाएगा। भारत और चीन के संबंधों में भी लंबे समय से तलछी हावी रही है। पिछले साल अक्टूबर में दोनों देशों के बीच वार्ता से संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में कुछ सहमति बनी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक टैरिफ नीति ने भी दोनों देशों को परस्पर हितों की पूर्ति के लिए साथ आने के लिए कुछ हद तक प्रेरित किया है। परिणामस्वरूप संबंधों में कुछ सहजता का भाव बनता दिखा है। कैलास-मानसरोवर यात्रा भी पांच साल बाद फिर से आरंभ हुई है। इस सबके बावजूद इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान का पहलू चीन के साथ संबंधों में सदैव एक रोड़ा बना रहेगा। चीन अपने हितों की पूर्ति के लिए भारत को भाव तो देना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान की कीमत पर नहीं। इसलिए भारत को भी चीन के साथ सतर्कता के साथ आगे बढ़ना होगा। पाकिस्तान के अलावा खुद चीन का पिछला रिकार्ड भी इस सतर्कता की आवश्यकता को मुखरता से रेखांकित करता है। यह परिस्थितियों में भारत चीन के साथ तात्कालिक एवं मध्यम अवधि में कुछ बिंदुओं पर आगे बढ़ सकता है, लेकिन दीर्घकालिक भविष्य के लिए उसे चीन की प्रभावी काट के लिए कोई स्थायी उपाय करना ही होगा। अमेरिका को पीछे छोड़कर विश्व व्यवस्था की सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में स्थापित होने को लालायित्व चिन कभी नहीं चाहेगा कि उसके पड़ोस में भारत जैसी किसी बड़ी ताकत का उभार हो। यह सुनिश्चित करने में वह अपने स्तर पर तो प्रयास करेगा ही, लेकिन समय-समय पर भारत को परेशान करने के लिए पाकिस्तान का भी इस्तेमाल करता रहेगा। आपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान को मिली लोनी मदद के संकेत सामने आए हैं। इसलिए भारत को इस दोहरी चुनौती से निपटने के लिए सामरिक-रणनीतिक के अलावा कूटनीतिक एवं आर्थिक विकल्प भी तलाशने होंगे। किंगदाओ में यह झलक भी देखने को मिली कि चीन-पाकिस्तान की मौजूदगी वाले मंच पर भारत के लिए गुंजाइश सीमित होती जाएगी।



✍ मनोज कुमार मिश्र

भाजपा और कांग्रेस विरोधी अनेक बुद्धिजीवियों के प्रभाव में आकर केजरीवाल ने 2014 में देश भर में लोकसभा चुनाव लड़ना तय किया। भारी पराजय के बाद अपने लोगों के गुस्सा से बचने के लिए जमानत तुड़वाकर जेल गए। 2015 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारी सफलता के बावजूद रामलीला मैदान में दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेते हुए कहा कि उन्हें दिल्ली की जनता से जनादेश उनकी सेवा करने के लिए मिला है, वे दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगे। तब से लेकर अब तक उनके बयान और दावों में कितनी बार और क्यों बदलाव हुआ, यह लंबा किस्सा है। हर रोज मीडिया की सुर्खियों में रहने वाले अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सत्ता से बाहर होने और खुद चुनाव हारने के बाद गाहे-बगाहे दिल्ली में सार्वजनिक रूप से दिख जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि वे राज्यसभा के सदस्य बनने के जुगाड़ में हैं। लेकिन, उनके घर बैठने से दिल्ली विधानसभा चुनाव के कुछ ही महीनों में आआपा के वजूद पर ही सवाल उठने लगे हैं। जो हालात बनते जा रहे हैं, उसमें केजरीवाल की तुलना विदेशी घुसपैठ के खिलाफ आंदोलन वलाकर सीधे छत्र आंदोलन से असम गण परिषद राजनीतिक दल बनाकर विधानसभा चुनाव जीतकर 1985 में असम के मुख्यमंत्री बने प्रफुल्ल कुमार महंत से की जाने लगी है।

14 फरवरी 2014 को 49 दिन की सरकार जाने के कुछ ही दिनों बाद आम आदमी पार्टी (आआपा) के अरविंद केजरीवाल के बाद दूसरे नंबर के नेता मनीष सिसोदिया ने अपने मयूर विहार, फेज- दो के घर पर मुझे मिलने के लिए बुलाया था। करीब घंटे भर उनसे विभिन्न विषयों पर बात होती रही। उनकी पूरी बातचीत का निचोड़ यह था कि हम और हमारी पार्टी सत्ता के लिए बने हैं। पार्टी के सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी छोटी है। हम तो भाजपा नेता डॉ. हर्षवर्धन को अपने साथ लाकर मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाना चाहते हैं, वे इसके लिए तैयार नहीं हैं (वैसे डॉ. हर्षवर्धन ने इसे पूरी तरह से निराधार बताया)। इस बातचीत के बाद सिसोदिया से अलग मिलने का मौका न मिला। लेकिन, बाद के घटनाक्रम ने एक बात तो साबित कर दी कि अरविंद केजरीवाल सत्ता के बिना नहीं रह सकते हैं और उनकी महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री बनने की है। भाजपा और कांग्रेस विरोधी अनेक बुद्धिजीवियों के प्रभाव में आकर केजरीवाल ने 2014 में देश भर में लोकसभा चुनाव लड़ना तय किया। भारी पराजय के बाद अपने लोगों के गुस्सा से बचने के लिए जमानत तुड़वाकर जेल गए। 2015 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारी सफलता के बावजूद रामलीला मैदान में दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेते हुए कहा कि उन्हें दिल्ली की जनता से जनादेश उनकी सेवा करने के लिए मिला है, वे दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगे। तब से लेकर अब तक उनके बयान और दावों में कितनी बार और क्यों बदलाव हुआ, यह लंबा किस्सा है। हर रोज मीडिया की सुर्खियों में रहने वाले अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सत्ता से बाहर होने और खुद चुनाव हारने के बाद गाहे-बगाहे दिल्ली में सार्वजनिक रूप से दिख जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि वे राज्यसभा के सदस्य बनने के जुगाड़ में हैं। लेकिन, उनके घर बैठने से दिल्ली विधानसभा चुनाव के कुछ ही महीनों में आआपा के वजूद पर ही सवाल उठने लगे हैं। जो हालात बनते जा रहे हैं, उसमें केजरीवाल की तुलना विदेशी घुसपैठ के खिलाफ आंदोलन चलाकर सीधे छत्र आंदोलन से असम गण परिषद राजनीतिक



दल बनाकर विधानसभा चुनाव जीतकर 1985 में असम के मुख्यमंत्री बने प्रफुल्ल कुमार महंत से की जाने लगी है। आज की तारीख में महंत की असम की राजनीति में कोई चर्चा तक नहीं होती है। 2011 के दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ समाजसेवी अन्ना हजारे के आंदोलन में शामिल अनेक नेताओं ने हजारों के मना करने के बावजूद 26 अक्टूबर 2012 को आम आदमी पार्टी के नाम से राजनीतिक दल बनाकर 2013 में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ना तय किया। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में 2013 का विधानसभा चुनाव लड़ा गया। पहले ही चुनाव में बिजली-पानी फ्री का मुद्दा कारगर हुआ। आआपा को 70 सदस्यों वाली विधानसभा में करीब 30 फीसद वोट और 28 सीटें मिली। भाजपा ने करीब 34 फीसद वोट के साथ 32 सीटें जीती और दिल्ली में 15 साल तक शासन करने वाली कांग्रेस को 24.50 फीसद वोट के साथ महज आठ सीटें मिलीं। भाजपा के मना करने पर आआपा ने कांग्रेस से बिना मांगे समर्थन से सरकार बनाई। नियम का पालन किए बिना लोकपाल विधेयक विधानसभा में पेश करने से रोके जाने के खिलाफ 49 दिन पुरानी सरकार ने इस्तीफा दिया। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा। 2014 के लोकसभा चुनाव में आआपा ने देश भर में चुनाव लड़ना तय किया। खुद केजरीवाल भाजपा के प्रधानमंत्री के घोषित उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनारस चुनाव लड़ने पहुंच गए। वे तो बुरी तरह से हारे ही आआपा के ज्योत्पल प्रमुख नेता लोकसभा चुनाव लड़े और पराजित हुए। केवल पंजाब में चार सीट आआपा जीत

पाई। बाद में उसमें से दो सांसद आआपा से अलग हो गए और 2019 के लोकसभा चुनाव में केवल अभी के मुख्यमंत्री भगवंत मान चुनाव जीते। 2024 में उसे केवल पंजाब में ही तीन सीटें मिलीं। 2014 के चुनाव में केजरीवाल ने बड़ा सपना देखा था, वे परिणाम से इतने आहत हुए थे कि कार्यकर्ताओं का गुस्सा शांत करने के लिए एकरन जमानत तुड़वाकर जेल गए। इतना ही नहीं एक-एक करके पार्टी के दिग्गजों-पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण, वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, प्रो. आनंद कुमार इत्यादि को पार्टी से बाहर किया। बाद में कुमार विश्वास समेत अनेक दिग्गज नेता बाहर हुए। कहा गया कि आआपा में वही रह सकता है, जो केजरीवाल के किसी फैसले पर सवाल न उठाए। बावजूद इसके, आआपा को कई बड़ी सफलता मिल गई। कांग्रेस की कमजोरी और भाजपा की अधूरी तैयारी के चलते और बिजली-पानी फ्री करने के वादे ने आप को 2015 के चुनाव में दिल्ली विधानसभा में रिकार्ड 54 फीसदी वोट के साथ 67 सीटों पर जीत दिलावा दी। उस चुनाव के बाद पार्टी में अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक कद और बढ़ गया। दोबारा मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने दिल्ली से बाहर पार्टी को न ले जाने का घोषणा कर दी। उन्होंने यह साबित कर दिया कि पार्टी को वोट उनके नाम से मिलते हैं। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में फिर उन्होंने रिकार्ड 54 फीसद वोट के साथ 62 सीटें जीती। 2017 के गोवा विधानसभा चुनाव में तो आआपा को कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन पंजाब में बेहतर नतीजे मिले। 117 सीटों की विधानसभा में कांग्रेस को 77

सीटें और आआपा को 20 सीटें मिली। इस बार आआपा ने शानदार जीत दर्ज की। उसे न केवल 92 सीटें मिली और उसकी दिल्ली से बाहर सरकार बनी। गुजरात और गोवा में चुनाव लड़कर आआपा अखिल भारतीय पार्टी बन गई। सत्ता ने उन्हें आम आदमी से खास आदमी बना दिया। नेता अरविंद केजरीवाल अपने पुराने वादे ही नहीं भूले, आम नेताओं से आगे निकलकर सरकारी कोठी को भव्य कोठी (विपक्षी दल शीशमहल कहते हैं) बनाकर रहने लगे। दिल्ली सचिवालय के अपने आधुनिक कार्यालय में भी उन्होंने करोड़ों रुपये खर्च करके काफी बदलाव कर उसे भी आलीशान बनवाया। उन्होंने जंतर-मंतर, रामलीला मैदान में लोगों के बीच जाना छोड़ ही दिया था। सुरक्षा के भारी ताम-झाम से उनकी लोगों से दूरी बढ़ी और जिस वीआईपी कल्चर का विरोध करके राजनीति में आए उसी कल्चर के प्रतीक बन गए। कट्टर ईमानदार राजनीति का दावा करने वाले केजरीवाल और उनकी पार्टी के शराब घोटाले आदि भ्रष्टाचार में फंसने के बाद उन्हें उस जंतर-मंतर की याद आई, जहां से उन्होंने अपने राजनीतिक गुरु अण्णा हजारे के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चलाया था। शराब घोटाले में कई बड़े नेताओं के जेल जाने के बाद खुद केजरावाल जेल गए। उन्होंने जेल से सरकार चलाने का अनोखा रिकार्ड बनाया। विधानसभा चुनाव से कुछ ही दिन नया राजनीतिक दांव चलते हुए धुर वामपंथी माता-पिता की संतान आतिशी को पहले मुख्यमंत्री और विधानसभा चुनाव हारने के बाद विश्व का नेता बना दिया। भाजपा और कांग्रेस आदि दल आआपा पर शहरी नक्सली होने का आरोप लगाते रहे हैं। आआपा से बागी हो गई राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने आतिशी के मुख्यमंत्री बनाने पर उनके अभिभावकों और खुद आतिशी के धुर वामपंथी होने का सवाल उठाया। 2025 के विधानसभा चुनाव में एक यह भी मुद्दा बना। 2024 का लोकसभा चुनाव और 2015 के विधानसभा चुनाव में केजरीवाल ने अपने को प्रताड़ित करने का मुद्दा बनाने की असफल कोशिश की। 70 सदस्यों वाली विधानसभा चुनाव में भाजपा 48 सीटों के साथ 27 साल बाद सत्ता में लौटी।

# सैन्य महाशक्ति बनने की संभावनाएं

आज रेयर अर्थ पर चीन का दबदबा वैश्विक चुनौती है। भारत सहित कई देशों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षित करने के लिए इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पहली बार मोदी सरकार ने रेयर अर्थ पर आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम उठाए हैं। यह आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए जरूरी भी है। भारत और अमेरिका सहित अनेक देश इस कवायद में लगे हुए हैं। रेयर अर्थ धरती के गर्भ में पाए जाने वाले दुर्लभ खनिज हैं। इनके बगैर ऑटोमोबाइल और सैन्य-रक्षा सहित विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का निर्माण संभव नहीं। रेयर अर्थ की श्रेणी में आने वाले दुर्लभ खनिज केवल वाणिज्यिक, औद्योगिक संसाधन मात्र नहीं हैं, ये तकनीकी संप्रभुता, रक्षा तैयारियों और भविष्य की औद्योगिक, आर्थिक व सैन्य महाशक्ति बनने की संभावनाओं की नींव हैं। इसमें भी रेयर अर्थ मैग्नेट खासा महत्वपूर्ण है। रेयर अर्थ मेटल 17 धातु तत्वों का एक

समूह है। इसमें 15 लैंथेनाइड्स धातुओं के अलावा स्कैंडियम और यिट्रियम शामिल हैं। इसमें चुंबकीय, ल्यूमिनसंट और इलेक्ट्रोकेमिकल के विषय गुण होते हैं, जिनका उपयोग आधुनिक उच्च तकनीक उद्योग में किया जाता है। स्मार्टफोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के साथ मिसाइल, रडार और अत्याधुनिक हथियार बनाने के लिए दुर्लभ खनिज ही चाहिए। इसके अलावा रिन्यूबल एनर्जी, विंड टर्बाइन और सोलर पैनल, सुपर कंडक्टर, हाइ प्लसम, मैग्नेट, इलेक्ट्रिक पॉलिसिंग, ऑयल, रिफाइनरी में केटिलिट, हाइब्रिड कलर कंपोनेंट एवं बैटरी, लैजर, एप्रोप्रेस के लिए भी ये अनिवार्य तत्व हैं। रेयर अर्थ मैग्नेट सामान्य आवरण मैग्नेट से 20 गुना अधिक ताकतवर होता है और कारों तथा कई अन्य उपकरणों में लगने वाली इलेक्ट्रिक मोटोर्स को बनाने के लिए जरूरी है। यूएस भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण डेटा पर आधारित एक नए ग्लोबल मैप के मुताबिक यूं तो कई देशों में इन

दुर्लभ तत्वों के भंडार हैं, लेकिन सर्वाधिक चीन में 44 मिलियन मीट्रिक टन भंडार है। चीन के बाद अफ्रीका,मोरक्को और दक्षिण अफ्रीका में प्रचुर मात्रा में जस्ता, लिथियम और कोबाल्ट के भंडार हैं, जो रिन्यूबल एनर्जी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। वहीं चिली और ब्राजील में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आवश्यक लिथियम भंडार हैं, तो यूक्रेन में टाइटेनियम और लिथियम और ग्रीनलैंड में दुर्लभ अर्थ मेटल्स और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं। दिक्कत यह है कि इन देशों में इसकी खुदाई और प्रोसेसिंग बहुत महंगी है। इससे भारी मात्रा में प्रदूषण भी निकलता है। इन सबमें चीन के पास ही इनकी प्रोसेसिंग की क्षमता है। वर्तमान में दुर्लभ पृथ्वी धातुओं का 61 प्रतिशत भंडार चीन में है और पूरी दुनिया में 90 फीसदी वही निर्यात करता है। इन तत्वों को एक-दूसरे से अलग करना बेहद जटिल है। इस्मीलए इन्हें रेयर माना जाता है। रेयर अर्थ की वैश्विक सप्लाई चेन में चीन का दबदबा है।

आधुनिक इंडस्ट्री में इनका महत्व यों समझा जा सकता है कि चीन ने जब अप्रैल में रेयर अर्थ मैग्नेट समेत छह तरह के बहुमूल्य धातुओं के निर्यात पर रोक लगाये का फैसला किया तो वैश्विक कंपनियों में खलबली मच गई और ऑटोमोबाइल उद्योग को विशेष रूप से झटका लगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाले शक्तिशाली इंजन मैग्नेट नियोडिमियम से बनते हैं। भारत में भी टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज मोटर्स दबाव में आए। सुजुकी कंपनी को अपनी स्विफ्ट कार का निर्माण कुछ समय के लिए स्थगित करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि भारत में ये दुर्लभ तत्व नहीं मिलते। भारत के पास तो विश्व में पांचवां सबसे बड़ा दुर्लभ खनिज भंडार है- करीब 6.9 मिलियन मीट्रिक टन। दुनिया में भारत की हिस्सेदारी छह फीसद है। इनमें केरल में थोरियम सैंड के अलावा आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान में भी इसके भंडार हैं। लेकिन, दुनिया भर की आपूर्ति का भारत में महज

को निलंबित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड द्वारा खनन किए गए दुर्लभ खनिज, विशेषकर नियोडिमियम जापान भेजे जाते थे, लेकिन भारत ने तय किया है कि वह अपने घरेलू उद्योगों की जरूरतों को प्राथमिकता देगा और चीन पर निर्भरता कम करेगा। इसी उद्देश्य के साथ इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड ने सरकार से घरेलू स्तर पर प्रसंस्करण और रिफाइनिंग की क्षमता विकसित करने के लिए चार नए खदानों की मंजूरी मांगी है। इसी रणनीति के तहत ओडिशा में एक एक्सट्रेक्शन प्लांट और केरल में एक रिफाइनिंग यूनिट भी स्थापित की गई है। राजस्थान के जोधपुर संभाग के बालोतरा क्षेत्र की सिवाना और आसपास की पहाड़ियों में इन दुर्लभ खनिजों की मौजूदगी पर केंद्र सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग की आधिकारिक पुष्टि के बाद जोधपुर में रेअर अर्थ एक्सप्लोरेशन सेंटर बनाने का प्रस्ताव भी सरकार के पास है।

## Social Media Corner

### सब के हक में...

उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक यह समय कई पवित्र यात्राओं की है, जिनमें एक भारत-श्रेष्ठ भारत का भाव निहित है। ये धार्मिक यात्राएं श्रद्धा और सेवा का महाअनुष्ठान भी हैं। तेलंगाना के भद्रावलम और कर्नाटक के कलहुरी सहित देशभर की हमारी माताओं-बहनों और बेटियों की ऐसी कई कहानियां हैं, जो बताती हैं कि कैसे वे अपने साथ ही देश का भाग्य भी बदल रही हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट की सुमा उड्डेक जी ने यह साबित कर दिखाया है कि जज्बा हो तो कैसे हमारी माताएं-बहनें भी बिजनेस एगन बन सकती हैं।

(प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'एक्स' पर पोस्ट)

ये 18वीं सदी नहीं है, पर झारखंड के गांवों में हालात अभी भी वही हैं। सिमडेगा जिले के बुंदिया गांव में एक बुजुर्ग महिला गंगो देवी के कमर में गंभीर वोट आई, लेकिन गांव में न सड़क थी, न स्वास्थ्य सुविधा, न एम्बुलेंस पहुंची। मजबूर परिजन खात पर लादकर तीन किलोमीटर पैदल चले। यमों की बात ये है कि ये सब उस राज्य में हो रहा है, जहाँ हैमंत सरकार ने इस साल बजट में स्वास्थ्य पर ₹34.97 करोड़ और सड़कों व पुलों के लिए ₹5300 करोड़ खर्च करने की घोषणा की थी। पिछले साल यही राशि ₹7223 करोड़ और ₹6389 करोड़ थी। इतना पैसा गया कहा? इसका जवाब तो हम सरकार को पता है। जब भ्रष्टाचार करने की बात आती है, तो हैमंत सरकार सुरसा से भी बड़ा मुंह खोल लेती है। लेकिन जब व्यवस्था को लेकर सवाल किया जाए, तो मुख्यमंत्री और मंत्री गूंगे बहरे बन जाते हैं।

(बाबूलाल मरांडी का 'एक्स' पर पोस्ट)

## विश्व की नई आर्थिक शक्ति बनेगा भारत

हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने देश को आर्थिक और सामरिक क्षेत्र में मजबूत बनाया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने महज 22 मिनट में स्वदेशी हथियारों से दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अब भारत को दुनिया की आर्थिक शक्ति बनने, पाकिस्तान और चीन की चुनौतियों से मुकाबले के लिए उन्नत एआई से संपन्न एवं आर्थिक रूप से सशक्त देश बनने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इजरायल-ईरान युद्ध और ऑपरेशन सिंदूर का विशेषण बताता है कि अब युद्ध में एआई और आर्थिक ताकत की अहमियत बढ़ गई है और परमाणु हमले की धमकी बेअसर साबित हो रही है। चीूँकि शक्ति के माध्यम से ही शांति आती है और उससे भविष्य के युद्ध भी रोके जा सकते हैं, अतः भारत को हर मोर्चे पर शक्तिशाली बनाना होगा। इसके लिए जरूरी है सरकार, विज्ञानी, तकनीकी विशेषज्ञ, उद्यमी-कारोबारी और जनता एकजुटता दिखाए। भारतीय अर्थव्यवस्था जिस तेजी से बढ़ रही है, उसे देखते हुए देश की वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने की उम्मीद बढ़ी है। इजरायल-ईरान युद्ध की चुनौतियों के बीच भारत बहुआयामी आर्थिक सुधारों के बल पर मजबूती के साथ खड़ा है। इस युद्ध से कई देशों में पेट्रोल-डीजल के दाम में वृद्धि, खाद्यान्न सहित जरूरी वस्तुओं

की आपूर्ति में कमी और शेयर बाजार में गिरावट आई, वहीं भारत बेहतर स्थिति में रहा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के साथ संघर्ष का भी भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ा। भारत का बड़ा घरेलू बाजार, निर्यात पर कम निर्भरता, सरकार के भारी पूंजीगत व्यय, बढ़ती क्रय शक्ति और कृषि क्षेत्र में सफलता ने देश को बाहरी आर्थिक झटकों से झेलने में सक्षम बनाया है। युद्ध के दौर में भी भारत के निर्यात बढ़े और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है। इजरायल-ईरान युद्ध से जहां दुनिया में महंगाई बढ़ी, वहीं भारत में घटी। भारत की खुदरा महंगाई दर महज 2.82 प्रतिशत और थोक महंगाई दर महज 0.39 प्रतिशत है। यह पिछले 14 महीनों का सबसे निचला स्तर है। देश के खाद्यान्न भंडार में एक साल से भी अधिक की जरूरतों को पूरा करने लायक गेहूं और चावल हैं। कृषि उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस वर्ष खाद्यान्न उत्पादन लगभग 6.5 प्रतिशत बढ़कर 35.39 करोड़ टन के रिकार्ड स्तर पर पहुंच सकता है। युद्ध के बीच भी भारत पर दुनिया का आर्थिक विश्वास बना रहा। इस समय भारत के पास 699 अरब डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा भंडार है। भारत की विकास दर चालू वित्त वर्ष 2025-26 में 6.5 प्रतिशत रहेगी। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) की विश्व आर्थिक परिदृश्य से

जुड़ी रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2025 में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनते हुए दिखाई देगा। भारत को दुनिया की नई आर्थिक शक्ति बनाने के लिए कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए। चीन से आयात में कमी लाकर व्यापार घाटा निर्यातित किया जाना चाहिए। चीन के साथ द्विपक्षीय कारोबार में भारत लगातार घाटे की स्थिति में बना हुआ है। वित्त वर्ष 2024-25 में चीन के साथ व्यापार घाटा बढ़कर 99.2 अरब डॉलर हो गया, जो 2023-24 में 85.07 अरब डॉलर था। ब्रिटेन के बाद अब अमेरिका और यूरोपीय संघ से नए मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) और द्विपक्षीय व्यापार समझौते कर व्यापार घाटे में कमी लाई जा सकती है। भारत को ओमान, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, इजरायल सहित खाड़ी के प्रमुख देशों के साथ भी एफटीए को शीघ्रतापूर्वक अंतिम रूप देना चाहिए। सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम (एमएसएमई) तेज विकास एवं रोजगार के लिए एक कारगर माध्यम बन सकते हैं। एमएसएमई निर्यात बढ़ाते हुए आयात निर्यात करके आर्थिक चिंताएं कम कर सकते हैं। इस समय भारत का सेवा निर्यात तेजी से बढ़ रहा है। इसके कारण भारत को सेवा निर्यात की वैश्विक राजधानी के रूप में देखा जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का सेवा निर्यात करीब 387.5 अरब डॉलर रहा।

## फुस्स रणनीतिक दांव

ईरान और इजरायल के बीच 12 दिन का युद्ध तनावपूर्ण संघर्षविराम के साथ खत्म हुआ। इजरायल का दावा है कि उसने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बरसों पीछे धकेल दिया है। लेकिन, हकीकत कहीं ज्यादा जटिल है। ईरान ने भारी नुकसान झेला है। उसके मुख्य परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया, शीर्ष कमान का बड़ा हिस्सा खत्म कर दिया गया और उसके हवाई रक्षा उपाय वस्तुतः अप्रभावी साबित हुए। कुल 600 से ज्यादा लोग, ज्यादातर असैनिक मारे गए। ईरान ने जो गंवैया है, उसे दोबारा बनाने में अगर दशकों नहीं, तो वर्षों जरूर लगेंगे। फिर भी जंग में जीत और हार केवल भौतिक नुकसान से नहीं मापा जाता। नुकसान और स्पष्ट शक्ति अस्तंतुलन के बावजूद तेहरान ने झुकने से इनकार कर दिया। ईरान सरकार 13 जून के शुरूआती सदमे से तेजी से बाहर निकली और बैलैस्टिक मिसाइल व ड्रोन हमलों के जरिए उसके लगातार जवाबी अभियान ने इजरायल की उस बहुस्तरीय हवाई प्रणाली की कमजोरियां उजागर कीं, जिसकी तारीफों के पुल बांधे जाते थे। वहां मौतें हुईं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेत-न्याहु, जिन्होंने पहले यह दावा किया कि उनके अभियान से ईरान में निजाम बदल सकता है, अखिरकार संघर्षविराम स्वीकार करने पर मजबूर हुए, जिसकी घोषणा अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु संश्रयों पर प्रहार के बाद हुई। तेहरान के बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान द्वारा कतर और इराक में अमेरिकी अड्डों पर प्रतीकात्मक प्रहार किए जाने के बाद संघर्ष मंद्धिम पड़ने का एलान किया। इस युद्ध के क्षेत्रीय व्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। ईरान ने खुद को इजरायल के प्रतिस्तुलन के रूप में दोबारा पेश किया है अन्यथा पश्चिम एशिया एकधुवीय ही था। तेहरान अपने पारंपरिक आयुद्ध भंडार को दोबारा बनाएगा। रूस और चीन के साथ रिश्ते मजबूत करेगा और इस क्षेत्र में संबंधों को नए सिरे से निर्मित करेगा।



## Election Commission must justify need for Bihar voter roll revision

The Election Commission of India (ECI) has announced a special intensive revision (SIR) of electoral rolls in Bihar just weeks before the likely notification of assembly elections. Such revisions, when conducted this close to polling, are extraordinary and must meet a high bar of justification. Yet no explanation, let alone evidence, has been offered for why this exercise is necessary now. Instead, the justification has taken a familiar and troubling shape: vague and unsubstantiated claims about “illegal voters” and “cross-border infiltration”.If this is not a damning indictment of the ministry of home affairs’ failure in protecting our borders, then it is definitely dog-whistling to create a pretext for the possibility of large-scale manipulation. The pattern is unmistakable and, to the opposition parties, the objective seems transparent: to manipulate voter rolls in a manner that systematically excludes minorities and the poor.This is not the first time such tactics have been deployed. In the run-up to the 2024 Lok Sabha elections and subsequent state elections in Maharashtra, lakhs of names were added to the electoral rolls in a short period. Opposition parties have raised valid concerns about the sudden spike and the unusually high late-evening turnout surges. The ECI has refused to release digital, machine-readable electoral rolls or polling-day CCTV footage.Also, ahead of the elections,right-wing commentators and academics belted out dubious ‘studies’ raising unfounded alarms about “illegal voters”. The exercise was repeated in Delhi right before the 2025 assembly elections. No other official data supported these claims.The fear-mongering in the name of “illegal migrants” or “bogus voters” used to be an ideological fringe position—it has become a tool of institutionalised disenfranchisement. This framing is used to justify aggressive and opaque revisions of electoral rolls that disproportionately target Muslim, Dalit and poor migrant communities. Now the ECI is echoing this language without any evidence and without accountability.There is a conspicuous absence of data and a deliberate invocation of public anxiety around border security and demographic change. The shift from dog-whistle politics to executive action—particularly by a constitutional body like the ECI—is a dangerous point.

The ECI must conduct a thorough and honest investigation into these allegations if India’s reputation as a democracy is to survive. The Constitution of India, under Article 324, entrusts the ECI with the conduct of free and fair elections. This does not just mean ballot secrecy or smooth polling logistics, it means ECI is constitutionally bound to protect the integrity of the electorate. This integrity is compromised when entire communities are asked to prove their right to vote without a shred of evidence against them.

These allegations are not speculation of losers. Research by Sabyasachi Das has demonstrated that in the 2019 Lok Sabha elections, BJP candidates won a disproportionate number of tightly contested seats, especially in BJP-ruled states. His analysis points to patterns consistent with the possibility of ‘manipulated’ rolls and irregularities in voter turnout data, not campaign strength. Economist Abusaleh Shariff, who was a member of the Sachar Committee, conducted voter roll audits in Karnataka that revealed nearly 20 percent of adult Muslims were missing from the electoral list, while 30-35 percent of Muslim households had only one listed voter. These patterns are not random— they are engineered exclusions.

## There’s something about Zohran K Mamdani

THE GREAT GAME: The Indian American New York mayoral candidate is perhaps reminding us of the idea of India, a sort of One Nation, Many Melting Pots

Who’s afraid of Zohran Kwame Mamdani? The 33-year-old Democrat candidate for New York mayor, whose many names are clearly more than a sum of its parts, has stirred and shaken half the globe in recent days — from Donald Trump (“he’s a Communist lunatic”) to Congress leader Abhishek Manu Singhvi (“when he opens his mouth, Pakistani PR takes the day off”), to frothing right-wingers like Kangana Ranaut (“he’s ready to wipe out Hinduism”).So what is it about this suited-booted young man that’s got the whirlwind in his sail? Let’s start with the names — the middle a reference to the Marxist Socialist first prime minister of Ghana; the last to his father, a Gujarati-Muslim scholar from Uganda, now a professor of international affairs and anthropology at Colombia University; the first to an Arabic word that means ‘a ray of light.’ As for his mother, she is the Hindu Punjabi documentary film-maker Mira Nair, who we all know has made both Monsoon Wedding and Mississippi Masala. Zohran’s wife, meanwhile, is Syrian and works in animation.The young man himself identifies as “democratic socialist”. He reached across New York City’s several divides — Black and South Asian, Hispanic and White and Chinese — to win 92 per cent of the Democratic vote to secure his seat as the party candidate earlier this week. He fought for basic issues like free bus fares, free child-care and controlled public housing rentals. He and his large band of volunteers invoked the old-fashioned principles of politics to go from house-to-house to ask for votes — a bit like what the RSS still does, what the Congress has forgotten to do, and what the Aam Aadmi Party once did back in the day.

Some of Zohran’s comments are, clearly, more hearsay than fact — and, yes, he should be far more careful, even if he’s 33. For example, he said last month that so many Muslims were killed in the 2002 riots in Gujarat that “people don’t even believe we exist anymore.” (In fact, there are 5.8 million Muslims in Gujarat.) He has likened PM Modi to Benjamin Netanyahu, who he described as a “war criminal.” (In 2022, the Supreme Court upheld the SIT’s clean chit and cleared the PM of any connection with the 2002 riots.)Notwithstanding the blood-letting in states like Mizoram — when the Indian Air Force in 1966 strafed Mizos seeking to secede from India — and later in Jammu & Kashmir, Punjab and Chhattisgarh, the Indian state has largely stayed away from carrying out mass violence against its own people; even in Chhattisgarh, Congress rulers gave up the ‘Salwa Judum’ vigilante movement it had orchestrated in 2005 to contain Left-wing extremism, which meant that tribals were killing tribals, as a bad idea.Manipur, in the last two years, remains a continuing exception.

And yet there’s something about Zohran. In 2023, as a



member of the New York state Assembly, he read from the notes of jailed student Umar Khalid about “the stillness in Tihar jail” — where he remains jailed, under several sections of the UAPA, for his alleged role in the 2020 Delhi riots. It will be 1,749 days, today, of Khalid’s incarceration, nearly five years of living in a cell, but charges have still not been framed against the young man. Perhaps some of Zohran’s incredible popularity is simply a reminder of what we once were — less cynical, braver, and determined to rearrange our societies so as to make them more egalitarian. He clearly likes to break down the walls, as Robert Frost once wrote, wondering what the functions of walls were — what were they walling in, or walling out. He likes to open the windows and let the air come in, as Gandhi once said was the function of windows.In an interview with Vogue India in 2020, soon after he became a member of the NY Assembly, Zohran talked about the run-up to his campaign when he was advised to be “less desi.” Instead, he spoke of his own

immigrant experience and called it “Roti and Roses.” There was a video called ‘Nani,’ a “woke granny,” featuring the star Madhur Jaffrey. As he walked across the city, he said, he listened to Meesha Shafi, Ali Sethi and Dr Zeus.

Perhaps the fact that he’s simply not embarrassed to be a bit of this and a bit of that, is what’s so charming about Zohran. He reminds us of the ceaseless ebb and flow that is the dharma of the Indian subcontinent — aham brahmami, I am brahman, the idea of a philosophy that incorporates the spurning of hierarchy, the inclination to pray to a multitude of gods or none, the refusal to be defined by inherited caste, class, gender.

Zohran’s father told The New York Times this week that when they lived in South Africa when he was a child and all the children in Zohran’s class were asked to identify themselves as White, Black or Coloured, Zohran described himself as “mustard.” Yellow. The colour of haldi in a khichri.

## Dumping threat looms elsewhere as India nears U.S. deal

While the contours of the proposed deal are unknown, it’s likely that it would enhance economic partnership, transform bilateral trade and lower tariffs, making products competitive across sectors

Donald Trump has dropped a big hint about signing a “very big” trade deal with India. The remarks, coming ahead of his July 9 deadline for striking deals or resuming ‘reciprocal’ tariffs, offer a significant relief for markets, policy makers and industry. Tariff-related uncertainties have triggered a massive sell-off in global and domestic equity markets, with foreign portfolio investments remaining volatile. While the contours of the proposed deal are unknown, it’s likely that it would enhance economic partnership, transform bilateral trade and lower tariffs, making products competitive across sectors such as energy, agriculture, defence and aviation. It’s also possible that India would gain market share in some American sectors owing to lower tariffs; although the gains would depend on India’s comparative advantage against other countries. The anticipated direct export loss is pegged at \$14 billion, amounting to 0.38 percent of India’s GDP, according to a working paper published by the National Institute of Public Finance and Policy.

The export basket might change, too. Some of India’s top 10 exports to the US—including electronic goods and gems & jewellery—may lose market share as competing



countries are subject to lower tariffs on these products. On the other hand, we may gain in the footwear, apparel, electrical machinery and toy markets. For instance, according to the NIPFP paper, China, Vietnam, Indonesia,

Italy and Cambodia account for 45.5 percent of the total in footwear exports to the US. Even if China is excluded, India can potentially corner a bigger share from Vietnam and Indonesia, which are subject to much higher tariffs of 46 percent and 32 percent, respectively. Similar opportunities exist in the furniture and sports equipment markets, too.At the same time, a multi-product, multi-country dumping threat looms over India. We should be watchful as China, Vietnam, Taiwan and others facing higher tariffs look to flood us with cheaper goods. While India reduces the tariff deficit with the US, it needs to offer calibrated concessions on select US goods like aerospace components. We should secure sector-specific exemptions, negotiate duty waivers for auto components and electronics, and diversify export markets away from the US, pursuing opportunities in the EU, the UK and ASEAN. Above all, India should strengthen domestic manufacturing, boost Make in India initiatives in key areas such as semiconductors, renewable energy and electronics to reduce import reliance and attract investments.

## Why India’s tailpipe pollution regime needs urgent reform

The air quality discourse appears to have increasingly turned punitive over the years. From banning older vehicles to restricting fuel access for “over-aged” vehicles, Delhi appears to be shifting all its environmental responsibility onto vehicle owners

The Commission for Air Quality Management recently directed that all end-of-life vehicles (ELV) will not be given fuel in Delhi starting July 1, 2025. While the move reflects an intent to curb vehicular pollution to address the Delhi-NCR’s chronic air quality crisis, it distracts from the deeper malaise: the failure to strictly enforce emission compliance on all vehicles on the road, not just the old ones. The air quality discourse appears to have increasingly turned punitive over the years. From banning older vehicles to restricting fuel access for “over-aged” vehicles, Delhi appears to be shifting all its environmental responsibility onto vehicle owners. Using vehicle age as a proxy for pollution, it overlooks the complex relationship between fuel, engine maintenance, and usage. A closer look into the systemic architecture such as unrenewed emission verification norms, regulatory gaps in testing frameworks, and poor enforcement of fuel efficiency standards reveals a troubling reality: India’s policy focus is targeting the tailpipe without reforming the pipeline.Age vs. Emissions: A Scientific Disjunct India’s air pollution control framework, influenced by European emission regulations and early 2000s Supreme Court rulings, has evolved into the Bharat Standards (BS). Judicial decisions force diesel vehicles off the roads after 10 years and petrol after 15, regardless of compliance with the set emission standards. This approach that prioritises age over actual emissions creates a disjunct: a well-maintained BS-IV vehicle running on petrol or diesel and regularly passing pollution tests must be

scrapped, while newer, but poorly maintained vehicles can continue to operate. Originally a thumb rule to compensate for limited available enforcement facilities, this blanket age-based criterion needs replacement by more granular, real-time metrics using emission data, owing to the changes in the air pollution index in Delhi-NCR. While in 2000s, studies attributed vehicular contributions to PM2.5 emissions at around 25 per cent, today, other denser sources such as construction dust, industrial emissions, and seasonal fires also contribute significantly to Delhi’s pollution.

Systemic Gaps in Enforcement

A 2022 CAG report also highlighted systemic deficiencies in Delhi’s vehicle fitness testing regime. As of 2021, automated testing centres comprised just 12 pc of testing capacity and were used at only 5 pc of their capacity. Manual centres, which rely on visual checks and cannot assess pollutants like NOx and PM2.5, handled 95 pc of tests. This opacity allows manipulation and undermines vehicle fitness declarations, rendering the PUC regime toothless.Furthermore, Delhi’s vehicle scrapping ecosystem is also ineffective with most ELVs ending up with unauthorised scrap dealers or are resold in states with laxer rules, merely shifting pollution elsewhere. Instead of modernising outdated frameworks using data-driven,



performance-based criteria, the government is forcing people to scrap or replace functional vehicles that may still meet existing testing norms. The approach also overlooks circular economy principles, and the embedded emissions associated with manufacturing new vehicles.

This blanket approach also unfairly affects senior citizens, who may be maintaining their vehicles well, drive sparingly, and use them for essential mobility. Additionally, it may be putting significant financial strain and inequitably penalises all those who have vehicles but prefer to use public transport.The Overlooked Efficiency Gap

Each year, Delhi-NCR faces severe air pollution, yet responses such as the Graded Response Action

Plan and the odd-even scheme remain short-term measures. A robust fuel and emissions control strategy is now critical — one that allows even older, well-maintained vehicles to remain compliant.Tailpipe emission verification is key and must be enforced rigorously along with tightening of the emission norms. Regular checks can identify high emitters and ensure compliance, addressing real-world emissions. With the planned installation of ANPR cameras, Delhi can create an automated system to restrict entry for high-emitting vehicles based on real-time data. Vehicle profiles (linked to VAHAN data) could include fuel type, age, emissions and PUC compliance status, and past testing history, supplemented by remote sensing devices. Such a system, free of human tampering, would allow well-maintained vehicles to continue while restricting true polluters – irrespective of the vehicle age.Furthermore, authorities can consider transferable scrapping credits linked to Aadhaar and vehicle registration, which can reward owners scrapping vehicles with incentives or offset allowances for new purchases or public transport usage. Such market-based mechanisms have a better chance of nudging behavioural change more efficiently than blanket bans.



Market Outlook: PMI, Auto Sales, FII Activity, Key Economic Data To Drive Stock Market This Week

**Mumbai.** Major factors, including auto sales figures, PMI data, Foreign Institutional Investor (FII) activity, and international economic updates, are expected to drive the Indian stock market this week. According to Bajaj Broking Research, several important economic data releases are scheduled between June 30 and July 4 in both India and the United States.

India's industrial production data for the month of May will be released on June 30, which will offer insights into the country's manufacturing output. The current account data for the first quarter is also expected to be announced on the same day. On July 1, S&P Global will publish India's Manufacturing PMI for June, while auto companies will release their monthly sales numbers. Later, on July 3, S&P Global will also release the Services PMI, providing a broader picture of the country's economic activity. Globally, key data from the US, such as Manufacturing PMI, jobless claims, non-farm payrolls, and unemployment figures, are expected next week. These indicators could significantly impact global markets. Meanwhile, Indian stock markets ended the week on a strong note. During the week, the 50-share index Nifty rose 525.40 points, or 2.09 per cent, to close at 25,637.80, while the 30-share index Sensex climbed 1,650.73 points, or 2 per cent, ending at 84,058.90.

The broader market also followed suit as the Nifty Midcap 100 index rose 2.40 per cent and the Nifty Smallcap 100 jumped 4.30 per cent. Sectorally, the Nifty Metal index surged 4.81 per cent, followed by Nifty Commodities (4.03 per cent) and Nifty Infra (3.37 per cent) as top performers. Analysts attribute the recent rally to easing geopolitical tensions between Iran and Israel and improving global stability. FIIs returned as net buyers last week, investing over Rs 4,423 crore in Indian equities. This was supported by falling crude oil prices, a stable rupee, and improving global risk appetite. Domestic Institutional Investors (DIIs) also remained net buyers, purchasing nearly Rs 12,390 crore worth of Indian equities.

**AI's Power Problem: Satya Nadella Warns Tech World to Use Energy Wisely as Microsoft Plans More Layoffs**

**New Delhi.** Microsoft CEO Satya Nadella is urging the tech industry to think hard about how much energy artificial intelligence (AI) uses and whether it truly benefits people. Speaking at Y Combinator's AI Startup School, Nadella said, "If you're going to use a lot of energy, you need to have a good reason. We can't just burn energy unless we are doing something useful with it." He stressed that AI should make real improvements in daily life, like making healthcare, education, or paperwork easier and faster.

Nadella pointed out that Microsoft, one of the world's biggest AI companies, used about 24 terawatt-hours of electricity in 2023—about as much as a small country. He said AI's true test is whether it solves real problems, such as helping hospitals discharge patients faster, saving both time and money, while Microsoft is betting big on AI, it's also cutting jobs. Over the past year, the company has laid off more than 6,000 employees as it reorganizes to focus on AI and cloud computing. More layoffs are expected soon, especially in the Xbox gaming division and sales teams, as Microsoft tries to boost profits after spending billions to buy Activision Blizzard. Nadella's message is clear: AI should not just be about new technology or profits—it must prove its worth by genuinely helping society, especially given its massive energy appetite. As Microsoft leads the AI race, it's also facing tough choices about jobs and the true cost of innovation.

**Digital Payments at Indian Post Offices: UPI Payments from August 2025**

**New Delhi.** Post offices across India will begin accepting digital payments at their counters starting August 2025, following the completion of a new IT system rollout, as per the official sources. The proposed move is expected to provide streamlined services to the customers, as per the PTI report.

Currently, post offices are unable to process digital payments as their accounts are not yet integrated with the Unified Payments Interface (UPI) system. National Payment Corporation of India (NPCI) provides the unified payment interface (UPI) services for better financial services and promotes the digital payment ecosystem in India. The Department of Posts is upgrading its IT infrastructure with new applications capable of handling transactions using dynamic QR codes. This rollout is expected to be completed across all post offices by August 2025," a government official told. As part of the IT 2.0 initiative, a pilot implementation of the system has already begun in the Karnataka circle. QR code-based booking for mail services has been successfully tested at the Mysore Head Office (HO), Bagalkot HO, and associated branch offices. Earlier, the department had introduced static QR codes at post office counters to facilitate digital payments. However, persistent technical issues and frequent customer complaints led to the discontinuation of that method. In India, post offices offer a wide spectrum of services, including mail delivery, speed post delivery, financial services like Post Office Savings Account, Recurring Deposit, Time Deposit, Monthly Income Scheme, Public Provident Fund, Senior Citizen Savings Scheme, Sukanya Samridhi Account, and Kisan Vikas Patra, etc. Additionally, post offices facilitate money transfer services and act as agents for government services.

Big Relief For NRIs: US Senate Cuts Proposed Remittance Tax From 3.5% To 1%

The revised proposal is expected to benefit around 2.9 million Indians living in the U.S.—the second-largest immigrant group in the country, according to the Migration Policy Institute.

**New Delhi.** Indian expats in the U.S. may soon get some relief on money transfers back home. The final draft of the 'One Big Beautiful Bill Act', backed by former President Donald Trump, now proposes slashing the remittance tax to just 1 per cent. This is a major reduction from earlier versions which suggested a 5 per cent levy, later brought down to 3.5 per



cent in the House proposal. The revised proposal is expected to benefit around 2.9 million Indians living in the U.S.—the second-largest immigrant group in the country, according to the Migration Policy Institute. As per The Economic Times, the Senate's latest draft, released on Friday, limits the 1 per cent remittance tax only to physical transfers

like cash, money orders, or cashier's cheques. Transfers made through bank accounts, credit or debit cards, and official financial channels will remain tax-free. Lloyd Pinto, Partner—US Tax at Grant Thornton Bharat, shared that Senate Republicans have released an updated draft of the proposed 'One Big Beautiful Bill Act' and are aiming to get it

passed by their self-imposed deadline of July 4. "The updated Senate version significantly changes the remittance transfer provisions that was passed by the House Republicans. In the latest Senate draft, the remittance transfer tax has been reduced to 1 per cent from the erstwhile proposal of 3.5 per cent," he said. Interestingly, the Senate's proposal does not include transfers made through bank accounts or using debit and credit cards issued in the U.S. The 1 per cent remittance tax will apply only to transfers where the sender uses cash, money orders, cashier's checks, or similar physical payment methods. This new rule is set to take effect from January 1, 2026. "This should come as a huge relief for the NRI community in the U.S.," said Pinto, "as they won't have to pay the remittance tax if they send money through accounts with designated U.S. banks or use debit or credit cards issued in the country."

FPIs On Course To Become Net Buyers In India For Third Month

**FPIs have fueled the recent bull run in the stock market following a sharp slump. By definition, Foreign Portfolio Investment involves investors buying foreign financial assets.**

**New Delhi.** Foreign Portfolio Investors (FPIs) are on course to become net buyers in Indian stock markets for the third straight month in June. In January, February, and March, they were net sellers throughout. Since April, however, they have turned net buyers in Indian equities. The latest data from the National Securities Depository Limited (NSDL) shows that FPIs have bought stocks worth ₹8,915 crore in June so far. In April and May, FPIs accumulated stocks worth ₹4,223 crore and ₹19,860 crore, respectively. FPIs have fueled the recent bull run in the stock market following a sharp slump. By definition, Foreign Portfolio Investment involves investors buying foreign financial assets. A declining dollar is always positive for emerging market equities; this encouraged FIIs to invest in India. The FII buying figure for June, including purchases through the exchange, primary market, and

other categories, stood at ₹8,915 crore through the 27th," said VK Vijayakumar, Chief Investment Strategist at Geojit Financial Services. "FIIs were buyers in financials, capital



goods, and realty stocks, while they were sellers in FMCG, consumer durables, and IT. FII buying has strengthened large-cap stocks, helping the Nifty and Sensex scale new highs for 2025. However, FIIs continued to sell in the bond market, and this trend is likely to continue due to the low yield differential between US and Indian

bonds. Ample liquidity and investor optimism have the potential to sustain the rally, though high valuations remain a limiting factor and could trigger profit booking," Vijayakumar added. The benchmark Sensex is now about 2,000 points below its all-time high of 85,978 points. At one point, the Sensex had fallen nearly 13,000 points from its peak. Recent FPI buying has helped support the indices. Indian stock markets have outperformed global markets in recent weeks, even as volatility persisted globally due to concerns over potential upcoming US reciprocal tariffs as the July 9 deadline approaches. A favorable inflation figure in India has also provided some support to domestic equity indices.

In 2024, both the Sensex and Nifty have posted gains of around 9–10%. In 2023, they rose by 16–17% cumulatively, while in 2022, the gains were a modest 3% each.

Indian Cement Sector Reaches 39.6 Million Metric Tonnes In May, Up 9%

**New Delhi.** The Indian cement sector reached 39.6 million metric tonnes (MT) in May, recorded a strong 9 per cent year-on-year (YoY) growth in volumes, according to a new report. The positive trend continued in the first two months of FY26, with volumes rising 8 per cent YoY to 78.7 million MT, according to the report by ICRA. For FY2025, cement volumes grew by 6.3 per cent YoY, totalling 453.0 million MT. ICRA projects a further 6–7 per cent growth in FY2026, with volumes expected to reach 480–485 million MT, driven by sustained demand from the housing and infrastructure sectors. Average cement prices saw an 8 per cent YoY increase in May 2025, reaching Rs 360 per bag, while prices for the first two months of FY2026 were up 7 per cent YoY. ICRA

anticipates an 80–150 basis points (bps) improvement in operating margins for its sample set of cement companies, rising to 16.3–17.0 per cent in



FY2026. The rating agency maintains a 'Stable' outlook for the Indian cement sector, reflecting confidence in continued demand and favourable cost conditions. The sector's resilience underscores its critical role in

supporting India's infrastructure and housing development. The combined Index of Eight Core Industries (ICI) increased by 0.7 per cent in May compared to the same month last year, according to the Ministry of Commerce and Industry data. The production of cement, steel, coal, and refinery products recorded positive growth last month. The final growth rate of the Index of Eight Core Industries for February, March and April was observed at 3.4, 4.5 and 1.0 per cent, respectively, said the ministry. Cement production rose by 9.2 per cent in May. Its cumulative index increased by 7.8 per cent during April to May, 2025–26 over the corresponding period of the previous year.

Policy miss: 71% of small manufacturers say government skill schemes haven't helped - Report

**New Delhi** A majority of small manufacturing enterprises in India say government-run skill-training initiatives are failing to reach them effectively, with 71 per cent reporting no benefits from such programmes, according to a report by Cushman & Wakefield. The survey, part of the firm's report 'Elevating India's Manufacturing Resilience: Charting the Path to Self-Reliance', highlights major gaps in talent support to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). According to news agency ANI, around 61 per cent of MSMEs overall said they had not received any support from government skill and talent programmes, while just 39 per cent confirmed any benefit. The disconnect is sharpest among smaller firms, those employing fewer than 500 people. The report notes that MSMEs employ four out of every five workers in the manufacturing sector and contribute to 40 per cent of the output. Yet, productivity remains low. A worker in an MSME generates only 14 per cent of the output compared to one in a large enterprise. Comparable firms in other emerging economies are already nearing

30 per cent output per worker, while the gap is even narrower in developed nations. Cushman & Wakefield's executive managing director Gautam Saraf said bridging capacity and cost gaps in areas like logistics, integrated facilities, and MSME productivity is vital. "Plug-and-play industrial parks, multimodal logistics networks, and improved land aggregation frameworks are not just enablers—they are essential levers for converting policy momentum into production-ready outcomes," he said, as quoted by ANI. Interestingly, while skill initiatives lag, infrastructure spending is having a strong impact. About 88 per cent of respondents said projects like Bharatmala, Sagarmala, Dedicated Freight Corridors, and the National Industrial Corridor Development had influenced their capital expenditure plans. In fact, 93 per cent reported better operating efficiency and profitability where modern industrial parks and



corridors are present, and 94 per cent of large enterprises credited infrastructure upgrades as key to their growth. However, long-term competitiveness is still threatened by high logistics costs, limited warehousing (0.2 sq. ft. per urban resident in India compared to 47.3 sq. ft. in the US), low domestic value addition (17 per cent vs China's 25 per cent), and skill shortages, especially in MSMEs. These challenges compound existing regulatory

burdens. In a separate study by TeamLease RegTech, a typical manufacturing MSME deals with over 1,450 compliance obligations annually, costing Rs 13–17 lakh per year. These span seven legal categories and involve 486 imprisonment clauses, many for procedural lapses. Rishi Agrawal, CEO of TeamLease RegTech, stressed that India must urgently reduce its "deeply entrenched hostility and inspector raj" to unshackle MSME growth. "We need to add compliance to India's DPI (Digital Public Infrastructure) stack," he added, as cited by ANI. The latest findings reinforce calls for a more holistic and MSME-centric policy approach—one that combines skill development with regulatory relief and infrastructure support to truly empower India's 6.45 crore MSMEs.





# Monsoon arrives early in India as Delhi sees light rains, floods in Uttarakhand

Scattered rain and thunderstorm warnings kept Delhi-NCR on alert as the monsoon tightened its grip on North India.

**Agency New Delhi.**  
The India Meteorological Department (IMD) on Sunday announced the arrival of the Monsoon over the entire country, including Delhi, nine days ahead of schedule. According to the IMD, the monsoon has now covered the remaining parts of Rajasthan, West Uttar Pradesh, Haryana and all of Delhi as of June 29, beating its usual timeline of July 8. The early onset brought light to moderate rain across Delhi-NCR on Saturday and Sunday, with showers and gusty winds reported in Rohini, Pitampura, Karawal Nagar, Rajouri Garden, Dwarka, IGI Airport and several other parts of the capital.  
Neighbouring areas in Haryana and western Uttar Pradesh, including Noida, also saw scattered rain and thunderstorms, with wind speeds

reaching up to 50 km/h in some places. Meanwhile, in Uttarakhand, the Char Dham Yatra has been suspended for the next 24 hours following a red alert for heavy rainfall. Garhwal Commissioner Vinay Shankar Pandey confirmed that pilgrims heading to Badrinath and Kedarnath are being stopped at Srinagar or Rudraprayag, while those bound for Yamunotri and Gangotri are being halted at Vikasnagar and Barkot. Pilgrims already at the shrines are being brought back under strict safety measures.  
The IMD has issued a red alert for today and tomorrow for Uttarkashi, Rudraprayag, Dehradun, Tehri, Pauri, Champawat, Bageshwar, Udham

Singh Nagar and Haridwar, warning of extremely heavy rainfall. An orange alert has also been declared across Uttarakhand for July 1 and 2, with the weather office cautioning that people



living in sensitive or low-lying areas face risks of waterlogging and landslides.  
In Uttarkashi, a cloudburst near Silai Band in Barkot triggered a landslide at a hotel construction site early Saturday morning.

According to District Magistrate Prashant Arya, nine labourers are missing after debris hit their shelter.  
Rescue operations by the State Disaster Response Force, National Disaster Response Force, police and local administration are underway despite continuous rain. Landslides have also blocked stretches of the Yamunotri and Gangotri highways.  
Himachal Pradesh is also on alert, with the weather department's Hydromet Division warning of moderate to high flash flood risk in parts of Bilaspur, Chamba, Hamirpur, Kangra, Kullu, Mandi, Shimla, Sirmour, Solan and Una districts over the next 24 hours. Heavy rainfall could trigger surface runoff and flooding in low-lying areas.

## Ten years, just two projects: Where does Delhi's slum rehabilitation policy stand?

**Agency New Delhi.**  
In 2015, Delhi introduced a rehabilitation policy that prioritised in-situ housing for slum dwellers, with relocation permitted only in "exceptional circumstances." However, a recent surge in demolitions has run contrary to the policy's intent, with many residents being shifted to far-flung locations.  
Major demolitions that have taken place after the BJP came to power are in Madras Camp (340 structures demolished), Bhoomiheen Camp (344 structures demolished), Jailervala Bagh Camp (300 structures demolished) and Taimoor Nagar (100 structures demolished). Eligible residents of Madras Camp have been offered housing in Narela, 50-odd km away.  
According to a list compiled by Basti Suraksha Manch, an organisation advocating for housing rights of slum dwellers in Delhi, many more demolitions have been taking place at an accelerated pace in recent months. "Since coming to power, the BJP government demolished around 30-40 slums. Currently, there are 5-10 settlements under threat of demolition. The government had given a slogan of 'Jahaan Jhuggi Wahin Makaan', but, instead, the poor are being removed from their homes," said Neelesh Kumar, a social activist and member of the group.

**What does the policy entail?**  
The rehabilitation of slums is governed by the Delhi Slum & Jhuggi Jhopri Rehabilitation and Relocation Policy, 2015, which was approved by the Cabinet in 2016. It prioritises in-situ rehabilitation — alternate accommodation has to be provided to a slum dweller on the same land or within a radius of 5 km.  
But under exceptional circumstances, in-situ rehabilitation need not be undertaken and relocation is considered. Such circumstances include a court order; if the slum encroaches on a street, road, footpath, railway safety zone, or a park; and if the encroached land is required by the land-owning agency for a public project that is urgent.

## Madhya Pradesh: Seven engineers suspended over 'faulty design' of over bridge in Bhopal

**Agency New Delhi.**  
The Madhya Pradesh government suspended seven engineers, including two chief engineers of the Public Works Department (PWD) for constructing a bridge with faulty design in Bhopal. Additionally, an inquiry has been launched against a retired superintendent engineer, as the said bridge has an unusual 90-degree turn. Apart from this, a construction company and a design consultant have been blacklisted by the government. A committee has been set up to make improvements in the bridge, Chief Minister Mohan Yadav said.

**Odd design of bridge a laughing stock**  
The newly built over bridge has been ridiculed by netizens, for its odd design. However, the engineers in the initial stages justified the flawed alignment to limited land availability near a metro station.  
The officials against whom action has been taken include chief engineers Sanjay Khande and G P Verma, in-charge executive engineer Javed Shakeel, in-charge sub-divisional officer Ravi Shukla, sub-engineer Umashankar Mishra, assistant engineer Shanul Saxena, in-charge executive engineer Shabana Rajjag and retired superintendent engineer M P Singh, said PWD additional chief secretary Neeraj Mandloi. The firms which was blacklisted is M/s Puneet Chaddha and design consultant M/s Dynamic Consultant.  
**Justification of 'faulty design'**  
The primary objective of the 18 crore ROB was improving the connectivity between Mahamai Ka Bagh, Pushpa Nagar and the station area with New Bhopal, aiding almost 3 lakh people.  
The officials involved in the construction process of the over bridge justified their act by claiming that they had no alternative but to construct the bridge in that way, due to the scarcity of land and the presence of a metro rail station nearby.

## AAIB probing sabotage angle too in Air India plane crash case: Union minister

**Agency Faridabad.**  
Minister of State for Civil Aviation Murlidhar Mohol has said that the Aircraft Accident Investigation Bureau (AAIB) is investigating all possible angles, including sabotage, in its probe into June 12 Air India plane crash in Ahmedabad, which killed 274 people. The minister added that the black box of the crashed Air India flight, which has been recovered, is currently in the custody of the AAIB and will remain within the country for a complete analysis. He made these remarks during a conclave held by.  
He said that the AAIB had started a full probe into the unfortunate incident. "It is being probed from all angles, including any possible sabotage. The CCTV footage are being reviewed and all angles are being assessed... several agencies are working on it," the minister pointed out. The Ahmedabad-London AI 171, belonging to Boeing Dreamliner 787-8 fleet, crashed seconds after taking off from Sardar Vallabhbhai Patel International Airport. Out of the 242 passengers and crew members on board, only one survived the crash.  
The minister said that the crash was a "rare case". "It has never happened that both engines have shut down together," he pointed out.  
His comments came amid claims by veteran pilots and aviation experts suggesting that a dual engine failure may have caused the plane to go down and burst into flames. He added that once the (probe) report is out, it will be possible to establish whether it was an engine problem or fuel supply issue or why both the engines had stopped functioning.  
"There is a CVR (cockpit voice recorder) in the black box which has stored the conversation between the two pilots. It is too early to say anything but whatever it is, it will come out. The report will come in three months," he pointed out.

## 'They've dumped us here, how will we survive?': What Delhi's bulldozers left behind — broken lives, bitter politics



**Agency New Delhi.**  
Perima stands outside the gate of a building in Sector G7, Narela's Pocket 4, packing sambar and chutney and arranging them on a plastic plate atop her pushcart. She wants to have everything ready — in case a customer shows up — so she doesn't waste time packing the order later. She stays in the flats behind her, provided by the Delhi Development Authority (DDA).  
But the home where she's lived since she was a child is 50-odd km away, at Madras Camp in Jangpura — now a mass of rubble. The colony was razed on June 1 after the Delhi High Court ordered the demolition of over 300 houses to clear the blocked Barapullah drain ahead of the monsoon.  
Like this slum cluster, several of the Capital's densely populated informal settlements — Bhoomiheen Camp, Taimoor Nagar, and Jailervala Bagh — have been razed over the last two months. While the courts and authorities cite encroachment on government land, those displaced — many of them work as daily-wage workers or house help — say they are being uprooted not just from their homes, but also from their livelihoods. Perima says she arrived at the flats in the Northwest Delhi suburb on the night of the demolition and set up the cart just three days ago. "Yesterday, it took me six hours to make the chutney because I had to travel to Jangpura to get the right chana dal. Here, there are no provision stores," she says.  
At Jangpura, she used to work as a domestic house help in four homes. "Yahan par laake daal diya, ab kaise guzaara karein, samajh hi nahi aa raha hai, har cheez mehengi hai yahan. (They have brought us here, how we will survive, we don't know. Everything is expensive here.) I used to earn Rs 20,000, but now I hardly earn anything."

## 3 dead, 50 injured in stampede during Puri Rath Yatra; Chief Minister apologises

**Puri stampede: The incident took place near Saradhabali, in front of the temple, where Lord Jagannath was seated on the chariot.**

**Agency New Delhi.**  
At least three people died and 50 others were injured in a stampede near Sri Gundicha Temple in Odisha's Puri during Lord Jagannath Rath Yatra. The incident occurred early Sunday morning, around 4-4.30 am amid heavy crowd. According to Puri District Collector Siddharth S Swain, the incident happened when hundreds of devotees had gathered near the Shree Gundicha Temple for darshan. The crowd suddenly surged and created a stampede-like situation.  
Emergency services responded quickly and the injured were taken to Puri District Hospital. Six of them are in critical condition.  
The victims have been identified as Pratiba Das Female (52), Premakanta Mohanty (78) and Basanti Sahu (42), all residents of Khurda district. Their bodies have been sent for postmortem.

The incident took place near Saradhabali, in front of the temple, where Lord Jagannath was seated on the chariot. The crowd became uncontrollable during the darshan and in the chaos several people fell and



were trampled. Authorities have launched an investigation into the cause of the incident. "We are looking into what triggered the rush and whether there were any lapses in crowd control," said

an official.  
**NEGLIGENCE UNFORGIVABLE: CHIEF MINISTER**  
Hours after the incident, Odisha Chief Minister expressed deep sorrow and said, "Due to the intense eagerness among devotees to have a glimpse of Mahaprabhu at Sharadhabali, an unfortunate incident occurred because of the resulting jostling and chaos. Personally, I and my government seek forgiveness from all Jagannath devotees."  
"We express our condolences to the families of those devotees whose lives were extinguished at Sharadhabali and pray to Mahaprabhu Jagannath to grant them the strength to bear this profound sorrow," he added. Calling the incident a result of serious negligence, the Chief Minister declared it "unforgivable" and ordered a prompt investigation into the security lapses. "Strict and exemplary action will be taken against those found responsible," he added.

## Jharkhand boy kills girlfriend, posts murder video online, then dies by suicide

**Police said the two teenagers had attended the Rath Yatra fair with friends, but a dispute on their way back allegedly led the teen to fatally stab the girl to death.**

**Agency New Delhi.**  
Lohardaga police recovered the body of an 17-year-old boy who died by suicide after allegedly murdering his teenage girlfriend. According to authorities, the boy attacked 14-year-old girl and killed her by slitting her throat with a knife. The incident took place in a forest area under the Serengdag police station limits.  
The boy recorded the horrific act, shared it on social media and later took his own life by hanging in a nearby jungle. Lohardaga SP Sadique Anwar Rizvi reported that the two teens, who were dating, attended

the Rath Yatra fair in Dandu village with friends. While returning in the evening, a dispute reportedly led



Jaynath to stab the girl multiple times, resulting in her death. Sources suggest the girlfriend had recently distanced herself from Jaynath, possibly fueling

his anger.  
Jaynath filmed the attack, took selfies with the girl's body and the blood-stained knife and posted the footage online before fleeing to the jungle. Villagers attempted to apprehend him, but he escaped and later hanged himself from a tree. The father of the victim, Ramdayal Kherwar, said his daughter, a student at Dunduru school, had gone to the fair with friends, including Jaynath. Bystanders tried to intervene during the attack but could not save her.  
Police recovered both bodies and sent them for post-mortem examination while continuing their investigation.

# India makes huge strides in QS 2026 Rankings, but has a long way to go

**Agency New Delhi.**  
India has scripted a huge achievement of late in the education field, which largely went unnoticed. This is because, unfortunately, education receives scarce attention in a country obsessed with politics, cricket, Bollywood and wars. New reforms and fresh initiatives in the education sector are rudimentary, but sadly, these are often given a short shrift. At a time when education in India is facing challenges galore comes a good news — which offers a ray of hope. The QS World University Rankings 2026, released on June 19, underscores India's strongest showing yet. Out of 8,000 educational institutions and universities from 106 countries, 1,501 were ranked this year, including 112 which made their entry for the first time.  
**A massive leap**  
What is heartening is that a record 54 institutions from India found place in this coveted list — the highest number to date for the country. This feat puts India ahead of countries like Germany (48) and Japan (47). It makes India the fourth most represented country in the rankings,

behind only the US, the UK, and China. It is to be noted that in 2014, merely 11 educational institutions from India made it in the prestigious rankings.  
So, it's a huge leap indeed — from 11 to 54. In other words, India has seen a massive 390 percent growth — nearly five times more — over the past 10 years. This amazing progress has come not just from top public institutions like the 12 IITs, Indian Institute of Science (IISc) Bengaluru, Delhi University, Anna University, and Delhi's Jawaharlal Nehru University, but also from several private universities that have made a huge impact.  
This is not just about numbers — it also shows that despite the prevailing challenges, the quality of Indian higher education is getting better and more competitive around the world.  
This year, almost 48 percent of Indian institutions in the QS rankings went up, while only 20 percent dropped. Undoubtedly, the implementation of the National Education Policy (NEP) — 2020

has gone a long way in bringing about this steady improvement. However, still more needs to be done.  
Education Minister Dharmendra Pradhan has rightly said that NEP 2020 is not just



changing the academic landscape, but transforming it in a truly revolutionary way. Prime Minister Narendra Modi said: "The QS World University Rankings have brought excellent news for our education system. Our government is committed to strengthening the ecosystem of research

and innovation for the benefit of India's youth."  
**Brilliant showing, but long road ahead**  
India's brilliant showing in the QS World University Rankings 2026 is laudable, and the steps taken to better the educator system are truly praiseworthy. However, we can't deny the fact that this success is still mostly restricted to IITs, central universities, and a few other prime institutions. A large number of universities nationwide are still reeling under fund crunch, dearth of qualified teachers, outdated labs, low research work, negligible focus on new ideas, and hardly any ties with foreign universities. It is also a matter of great concern that approximately 1.8 million Indian students are at presently studying at foreign universities, with an estimated Rs 5 lakh crore spent each year on their education. The pertinent question is: Can we prevent this trend of large-scale student migration by strengthening our higher education system and offering world-class opportunities within the country?



NEWS BOX

Ukraine says Russia launched its biggest aerial attack since the start of war

KYIV. Russia launched its biggest aerial attack against Ukraine overnight, a Ukrainian official said on Sunday, part of an escalating bombing campaign that has further dashed hopes for a breakthrough in efforts to end the 3-year-old war.

Russia fired a total of 537 aerial weapons at Ukraine, including 477 drones and decoys and 60 missiles, Ukraine's air force said. Of these, 249 were shot down and 226 were lost, likely having been electronically jammed.Yuriy Ihnat, head of communications for Ukraine's air force, told the Associated Press that the overnight onslaught was "the most massive air strike" on the country, taking into account both drones and various types of missiles. The attack targeted regions across Ukraine, including western Ukraine, far from the frontline.

Poland and allied countries scrambled aircraft to ensure the safety of Polish airspace, the Polish air force said Sunday.Kherson regional Gov. Oleksandr Prokudin said one person died in a drone strike. Six people were wounded in Cherkasy, including a child, according to regional Gov. Ihor Taburets.

In the Lviv region in the far west of Ukraine, a large-scale fire broke out at an industrial facility in the city of Drohobych following a drone attack that also forced parts of the city to lose power.The fresh attacks follow Russian President Vladimir Putin's saying Friday that Moscow is ready for a fresh round of direct peace talks in Istanbul. However, the war shows no signs of abating as US-led international peace efforts have so far produced no breakthrough.

Two recent rounds of talks between the Russian and Ukrainian delegations in Istanbul were brief and yielded no progress on reaching a settlement.

Long-range drone strikes have been a hallmark of the war, now in its fourth year. The race by both sides to develop increasingly sophisticated and deadlier drones has turned the conflict into a testing ground for new weaponry.

Iran judiciary says Israeli strike on Tehran's Evin prison killed 71

TEHRAN. An Israeli strike on Tehran's Evin prison during this month's 12-day war killed at least 71 people, Iran's judiciary said Sunday, days after a ceasefire ended hostilities between the two arch-foes.

The strike on Monday destroyed part of the administrative building at Evin, a large, heavily fortified complex in the north of Tehran, which rights groups say holds political prisoners and foreign nationals."According to official figures, 71 people were killed in the attack on Evin prison," said judiciary spokesman Asghar Jahangir of the attack, part of the bombardment campaign Israel launched on June 13.According to Jahangir, the victims at Evin included administrative staff, guards, prisoners and visiting relatives as well as people living nearby.

Images shared by the judiciary showed destroyed walls, collapsed ceilings, scattered debris, and broken surfaces across waiting areas at the facility.

The judiciary said that vin's medical centre and visiting rooms had been targeted.On Tuesday, a day after the strike, the judiciary said that the Iranian prison authority had transferred inmates out of Evin prison, without specifying their number or identifying them.

The inmates at Evin have included Nobel Peace Prize laureate Narges Mohammadi as well as several French nationals and other foreigners.

Japan launches climate change monitoring satellite on mainstay H2A rocket's last flight

TOKYO. Japan on Sunday successfully launched a climate change monitoring satellite on its mainstay H-2A rocket, which made its final flight before it is replaced by a new flagship model designed to be more cost competitive in the global space market.

The H-2A rocket lifted off from the Tanegashima Space Center in southwestern Japan, carrying the GOSAT-GW satellite as part of Tokyo's effort to mitigate climate change. The satellite was safely separated from the rocket and released into a planned orbit about 16 minutes later.Scientists and space officials at the control room exchanged hugs and handshakes to celebrate the successful launch, which was delayed by several days due to a malfunctioning of the rocket's electrical systems.Keiji Suzuki, a Mitsubishi Heavy Industries official in charge of rocket launch operations, said he was more nervous than ever for the final mission of the rocket, which has been his career work. "I've spent my entire life at work not to drop H-2A rocket... All I can say is I'm so relieved."

Sunday's launch marked the 50th and final flight for the H-2A, which has served as Japan's mainstay rocket to carry satellites and probes into space with a near-perfect record since its 2001 debut. After its retirement, it will be fully replaced by the H3, which is already in operation, as Japan's new main flagship.

"It is a deeply emotional moment for all of us at JAXA as a developer," Hiroshi Yamakawa, president of the Japan Aerospace Exploration Agency, told a news conference.The GOSAT-GW, or Global Observing SATellite for Greenhouse gases and Water cycle, is a third series in the mission to monitor carbon, methane and other greenhouse gasses in the atmosphere. Within one year, it will start distributing data such as sea surface temperature and precipitation with much higher resolution to users around the world, including the US National Oceanic and Atmospheric Administration, officials said.The liquid-fuel H-2A rocket with two solid-fuel sub-rockets developed by Japan Aerospace Exploration Agency has so far had 49 flights with a 98% success record, with only one failure in 2003. Mitsubishi Heavy has provided its launch operation since 2007.H-2A successfully carried into space many satellites and probes, including Japan's moon lander SLIM last year, and a popular Hayabusa2 spacecraft in 2014 to reach a distant asteroid, contributing to the country's space programs.

‘Kisses Yes, Bezos No’: Venice fumes as billionaire’s lavish wedding disrupts city

The demonstration contrasted with the expensive wedding bonanza, seen by critics as an affront to the lagoon city’s fragile environment and its citizens, overwhelmed by throngs of tourists.

VENICE. Hundreds of protesters marched through Venice's central streets on Saturday to say "No" to billionaire Jeff Bezos, his bride and their much-awaited wedding extravaganza, which reached its third and final day amid celebrity-crowded parties and the outcries of tired residents.On Friday, the world's fourth-richest man and his bride Lauren Sanchez Bezos tied the knot during a private ceremony with around 200 celebrity guests on the secluded island of San Giorgio.The wedding, however, angered many Venetians, with some

activists protesting it as an exploitation of the city by the billionaire Bezos, while ordinary residents suffer from overtourism, high housing costs and the constant threat of climate-induced flooding.As the two newlyweds prepared for the final party Saturday evening, hundreds of Venetians and protesters from across Italy filled Venice's tiny streets with colorful banners reading "Kisses Yes, Bezos No" and "No Bezos, no War." Venice has around 50,000 residents.The demonstration contrasted with the expensive wedding bonanza, seen by critics as an affront to the lagoon city's fragile environment and its citizens, overwhelmed by throngs of tourists.

"We are here to continue ruining the plans of these rich people, who accumulate money by exploiting many other people ... while the conditions of this city remain precarious," said Martina Vergnano, one of the demonstrators.The protest organizers claimed that their planned protest had forced the relocation of Saturday's party from a supposed initial location to a former medieval shipyard, the Arsenale.Bezos donated 1 million euros (\$1.17 million) each to three environmental research

organizations working to preserve Venice, according to Corila, the Venetian environmental research association.But many protesters blasted the move as a clear attempt to appease angry residents."We want a free Venice, which is finally



dedicated to its citizens. ... Those donations are just a misery and only aimed at clearing Bezos' conscience," said Flavio Cogo, a Venetian activist who joined Saturday's protest.Details of the exclusive wedding ceremony Friday night were a closely guarded secret, until Sánchez Bezos posted to Instagram a photo of herself beaming in a white gown as she

stood alongside a tuxedo-clad Bezos.Athletes, celebrities, influencers and business leaders converged to revel in extravagance that was as much a testament to the couple's love as to their extraordinary wealth.The star-studded guest list included

Oprah Winfrey and NFL great Tom Brady, along with Hollywood stars Leonardo Di Caprio and Orlando Bloom, tech entrepreneur and philanthropist Bill Gates and top socialites, including the Kardashian-Jenner clan.Ivanka Trump, her husband Jared Kushner and their three children also joined the celebrations.

The bride and groom stayed at the Aman Venice hotel on the Grand Canal, where Bezos posed for photos and Sanchez Bezos blew kisses to the press."The planet is burning but don't worry, here's the list of the 27 dresses of Lauren Sánchez," read one protest slogan, a reference to the bride's reported wedding weekend wardrobe. It featured a mermaid-lined wedding gown by Dolce & Gabbana and other Dolce Vita-inspired looks by Italian designers, including Schiaparelli and Bottega Veneta.

Rain-related incidents leave 38 dead in Pakistan; Khyber-Pakhtunkhwa bears the brunt

ISLAMABAD.Death toll in rain-related incidents in Pakistan has risen to 38 with 63 injured as pre-monsoon showers continued to wreak havoc in various parts of the country, officials said.The pre-monsoon spell began on June 26 and continued with intervals in different parts of the country, the National Disaster Management Authority (NDMA) said on Saturday night, adding that the Khyber-Pakhtunkhwa (KP) province in the northwest was the worst hit.

At least 19 people of the same family were killed when they were swept away by a flash flood on Friday in the Swat area of Khyber-Pakhtunkhwa. The provincial government of Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) came under immense criticism for failing to help the family, which took refuge on higher ground for an hour when surrounded by flood water, butwere

ultimately swept away.The provincial government suspended four officials and removed Swat Deputy Commissioner Shehzad Mahboob from his post for failing to save the



family.However, federal information minister Atta Tarar on Saturday demanded that the chief minister, Ali Amin Gandapur, should take responsibility for the deaths and resign.Another 12 people were killed in Punjab and seven in Sindh provinces

in rain-related incidents. While 41 people were injured in Punjab, 16 in Sindh and six in Khyber-Pakhtunkhwa in separate incidents.Among other losses, 63 houses were damaged and 30 animals were killed across the country. Roads and bridges were also damaged in the rains and floods. Rescue and rehabilitation efforts were going on to help those affected, the NDMA said.Scattered rains were expected in the next 24 hours and an alert has been issued for glacial lake outburst floods, urban flooding, and flash floods across various regions of Pakis-tan over the next 24 to 48 hours,NDMA added.

The NDMA has urged all provincial and district administrations to remain on high alert to deal with all emergencies. The monsoon weather system annually brings rains in the vast sub-continent region, including Pakistan.

'Bid to reshape CHP': Graft case piles pressure on Turkey's main opposition

The outcome could see several CHP figures -- including jailed Istanbul mayor Ekrem Imamoglu -- facing up to three years in prison and a political ban for graft, Turkish media reported.

ANKARA. A court hearing that could upend the leadership of Turkey's main opposition CHP is the latest bid to hobble the party behind a wave of spring protests that shook the government, analysts say.

The hearing, which takes place on Monday at an Ankara court, could render null and void the result of a leadership primary within the Republican People's Party (CHP) in November 2023 on grounds of alleged fraud -- thereby overturning the election of leader Özgür Özel.

In February, the Ankara public prosecutor opened an investigation

into allegations of vote buying at the congress which resulted in Ozel defeating longtime incumbent Kemal Kilicdaroglu.The CHP has denied the allegations.The outcome could see several CHP figures -- including jailed Istanbul mayor Ekrem Imamoglu --



facing up to three years in prison and a political ban for graft, Turkish media reported.And if the election result is cancelled, the party leadership would almost certainly revert to 76-year-old Kilicdaroglu.He was ousted five months after losing a bitterly fought presidential campaign against President Recep Tayyip Erdogan that was widely seen as the most important vote in generations, leaving the party in

crisis.

**Taming the opposition**

"This is a bid to reshape the CHP and create an opposition that is controlled by a government which is becoming more and more authoritarian," Berk Esen, a political science expert at Istanbul's Sabanci University, told AFP."This will provoke a split within the party, putting a weak, defeated leader in charge whom the voters don't want any more," he said.Kilicdaroglu has already said he would be willing to take on the party leadership again if the court overturned the primary result, sparking uproar within the CHP."It would be out of the question to not recognise such a verdict. Would it be better if a trustee was appointed to lead the party?" he said, also voicing his disapproval of the mass protests called by the CHP following Imamoglu's arrest and jailing in March.Widely seen as the only politician capable of defeating Erdogan at the ballot box, Imamoglu was arrested in connection with a graft and terror probe which the CHP has denounced as groundless.

Ex-Israeli PM Bennett says Netanyahu 'must go', blames him for 'divisions' in Israeli society

JERUSALEM. Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu must leave office, his predecessor Naftali Bennett has told a televised interview, refusing to say whether he intends to challenge the country's longest-serving leader in an election.In an interview with Israel's Channel 12 that aired on Saturday, former prime minister Bennett said Netanyahu "has been in power for 20 years... that's too much, it's not healthy."

"He bears...heavy responsibility for the divisions in Israeli society", Bennett said of growing rifts within Israel under Netanyahu, who has a strong support base but also staunch opponents who have demanded his departure including over his handling of the Gaza war since October 2023.etanyahu "must go", said the



former prime minister, a right-wing leader who in 2021 joined forces with Netanyahu critics to form a coalition that ousted him from the premiership after 12 consecutive years at the helm.But the fragile coalition government Bennett had led along with current opposition chief Yair Lapid collapsed after about a year. Snap elections ensued, and Netanyahu again assumed the premiership with backing from far-right and ultra-Orthodox Jewish parties.Bennett, who has taken time off from politics, has been rumoured to be planning a comeback, with public opinion polls suggesting he may have enough support to oust Netanyahu again.No vote is currently planned before late 2026, however, although early elections are common in Israel.In his Saturday interview, Bennett claimed credit for laying the groundwork for Israel's bombardment campaign earlier this month against Iranian nuclear and military sites.The decision to launch attacks against the Islamic republic "was very good" and "needed", said Bennett, claiming that the offensive would not have been possible without the work of his short-lived government.In Gaza, where Israel has waged war since Hamas's October 2023 attack, Bennett said the military has displayed "exceptional" performance but "the political management of the country" was "a catastrophe, a disaster".

What's in the latest version of Trump's 'big beautiful bill' now before US Senate

WASHINGTON. At some 940-pages, the legislation is a sprawling collection of tax breaks, spending cuts and other Republican priorities, including new money for national defense and deportations.Now it's up to Congress to decide whether President Donald Trump's signature domestic policy package will become law. Trump told Republicans, who hold majority power in the House and Senate, to skip their holiday vacations and deliver the bill by the Fourth of July.Senators were working through the weekend to pass the bill and send it back to the House for a final vote. Democrats are united against it.Here's the latest on what's in the bill. There could be changes as lawmakers negotiate.

**Tax cuts are the priority**

Republicans say the bill is crucial because there would be a massive tax increase after December when tax breaks from Trump's first term expire. The legislation contains roughly \$3.8 trillion in tax cuts.The existing tax rates and brackets would

become permanent under the bill. It temporarily would add new tax breaks that Trump campaigned on: no taxes on tips, overtime pay or some automotive loans, along with a bigger \$6,000 deduction in the Senate draft for older adults who earn no more than \$75,000 a year.It would boost the \$2,000 child tax credit to \$2,200 under the Senate proposal. Families at lower income levels would not see the full amount.A cap on state and local deductions, called SALT, would quadruple to \$40,000 for five years. It's a provision important to New York and other high tax states, though the House wanted it to last for 10 years.There are scores of business-related tax cuts.The wealthiest households would see a \$12,000 increase from the legislation, which would cost the poorest people \$1,600 a year, according to the nonpartisan Congressional Budget Office (CBO) analysis of the House's version. Middle-income taxpayers would see a tax break of \$500 to \$1,500, the CBO said.Money for deportations, border



wall and 'Golden Dome'The bill would provide some \$350 billion for Trump's border and national security agenda, including \$46 billion for the US-Mexico border wall and \$45 billion for 100,000 migrant detention facility beds, as he aims to fulfill his promise of the largest mass deportation operation in US history.Money would go for hiring 10,000 new Immigration and Customs Enforcement officers, with \$10,000 signing bonuses and a surge of Border Patrol officers, as well. The goal is to deport some 1 million people per year.The homeland security secretary would have a new \$10 billion fund for

grants for states that help with federal immigration enforcement and deportation actions. The attorney general would have \$3.5 billion for a similar fund, known as Bridging Immigration-related Deficits Experienced Nationwide, or BIDEN, referring to former Democratic President Joe Biden.To help pay for it all, immigrants would face various new fees, including when seeking asylum protections.For the Pentagon, the bill would provide billions for ship building, munitions systems, and quality of life measures for servicemen and women, as well as \$25 billion for the development of the Golden Dome missile defense system. The Defense Department would have \$1 billion for border security.How to pay for it? Cuts to Medicaid and other programsTo help partly offset the lost tax revenue and new spending, Republicans aim to cut back some long-running government programs: Medicaid, food stamps, green energy incentives and others.



NEWS BOX

WI vs AUS: ICC punishes Darren Sammy for criticising umpire Adrian Holdstock

West Indies head coach Darren Sammy has been fined by the ICC (International Cricket Council) for his disparaging remarks against third umpire Adrian Holdstock during the first Test against Australia in Barbados. Sammy had expressed his concerns over two contentious calls during Day 2 of the Test match, which went against the West Indies. He has been fined 15% of his match fee for a Level 1 breach of the ICC Code of Conduct. The former West Indies captain was found to have violated Article 2.7 of the Code, which pertains to “public criticism of, or inappropriate comment in relation to an incident occurring in an International Match or any Player, Player Support Personnel, Match Official or team participating in any International Match.”One demerit point has also been added to Sammy’s disciplinary record, with this being his first offence in a 24-month period. The West Indies head coach has accepted his sanction proposed by Match Referee Javagal Srinath for the charge levelled by on-field umpires Richard Kettleborough and Nitin Menon, third umpire Adrian Holdstock, and fourth umpire Gregory Brathwaite.Three decisions became the talking point of the Test match as on Day 1, Australia batter Travis Head was given a reprieve by TV umpire Adrian Holdstock after he ruled him not out on 53,



citing a lack of evidence on a clear catch by Shai Hope behind the stumps. Later on Day 2, Roston Chase was given out lbw against Pat Cummins, despite the cameras showing an inside edge onto the pads on replays.To add to West Indies’ woes, Shai Hope was given out against Beau Webster as a low take from wicketkeeper Alex Carey was ruled in Australia’s favour. Darren Sammy even met with match referee Javagal Srinath after Day 2 to express his concerns over the controversial decisions. "You don't want to get yourself in a situation where you're wondering about certain umpires. Is there something against this team? But when you see decision after decision, then it raises the question,” said Sammy at the end of the day’s play.

Carlos Alcaraz targets rare Wimbledon three-peat: Really want to win the title

New Delhi. Carlos Alcaraz said that he desperately wants to get his hands on the Wimbledon 2025 title. The young Spaniard is on the cusp of a major landmark with a chance to become only the fourth man after Bjorn Borg, Pete Sampras, Roger Federer and Novak Djokovic to complete a three-peat in the grass-court major.Last year, Alcaraz successfully defended his title after beating 24-time Grand Slam champion Djokovic in the final. The 22-year-old is in good stead, having recently won the HSBC Championships after beating Jiri Leheckka in the final. "I'm coming here thinking that I really want to win the title, I really want to lift the trophy, not thinking about how many players have won three Wimbledons in a row," Alcaraz



told the reporters on Saturday."I just want to be ready, to prepare myself in the best way possible to start the tournament with a lot of confidence. Obviously I feel a lot of confidence right now," he said."Two weeks could be really long in a Grand Slam but right now I'm not thinking about who I could join if I win three Wimbledons in a row," Alcaraz added.Since missing the Madrid Open due to injury, Alcaraz has won two titles on the trot. Earlier this month, he won his maiden French Open title after beating Jannik Sinner in the final, following which he won the HSBC Championships."The style that the people bring to the court when they play on grass, I think is so beautiful. The sound of the ball, the movement is really tough -- but when you get it, it's like you're flying.""It's just pretty to me because I really want to hit slices, dropshots, go to the net all the time and play aggressively. I think on grass it's the style that you have to play, so that's what I like the most," Alcaraz added.At Wimbledon, Alcaraz will kick off proceedings with his first-round match against Fabio Fognini of Italy on Monday, June 30.

Novak Djokovic figures Wimbledon gives him his best chance at a record 25th Grand Slam title

Djokovic has won seven championships at the grass-court major and come oh-so-close to making his total eight — the number Roger Federer won — but lost in the 2023 and 2024 finals to Carlos Alcaraz.

LONDON. It's become part of Novak Djokovic's routine now, particularly at Grand Slam tournaments: He shows up and gets asked — at the start of the event, during the event, after the event or sometimes all three — whether this will be his final appearance there.Happened again Saturday at Wimbledon, and his response was the same it tends to be, which essentially amounts to: Who can tell?"Whether it could be my 'last dance,'" the 24-time major champion began, repeating the phrase used by the reporter who posed the question, "I'm not sure — as I'm not sure about Roland Garros or any other Slam that I play next."And then Djokovic continued,

offering something of a mix of seemingly trying to quiet any talk about whether he truly is pondering retirement at age 38 while also being realistic about where things stand. "My wish is to play for several more years. I would love to be healthy physically and also mentally motivated to keep on playing at the highest level," he said. "That's the goal. But you never know at this stage."What Djokovic did concede is that the All England Club might offer the likeliest spot for him to gather one more Grand Slam singles title, which would allow him to raise his career haul to 25 — a number that no tennis player ever has reached."I would probably agree that Wimbledon could be the best chance, because of the results I had, because of how I feel, how I play in Wimbledon," said Djokovic, who faces Alexandre Muller in the first round Tuesday. "Just getting that extra push mentally and motivation to perform the best tennis at the highest level."Djokovic has won seven championships at the grass-court major and come oh-so-close to making his total eight — the number Roger Federer won, and one behind Martina Navratilova's record nine women's trophies — but lost in



the 2023 and 2024 finals to Carlos Alcaraz. All told, Djokovic has appeared in the title match each of the past six times the tournament was held (it was canceled in 2020 amid the COVID-19 pandemic), winning it in 2018, 2019, 2021 and 2022. His most recent Wimbledon loss came all the way back in 2017, when he was defeated in the quarterfinals by 2010 runner-up Tomas Berdych.As for the persistent questions about Djokovic's future, it's the same type of topic that was presented to Federer, Rafael Nadal and Serena Williams as those greats of the game neared their farewells. Now it's just Djokovic's turn. But just because he hasn't won a Grand Slam

trophy in more than 1 1/2 years — he collected three in 2023, capped by the U.S. Open that September — don't think that Djokovic isn't capable of grabbing another. As he reminded anyone listening Saturday, he made it to the semifinals at the Australian Open this January before stopping after one set because of a hamstring injury, and got to the final four at the French Open this month before losing to No. 1 Jannik Sinner. After that one, Djokovic took time as he left the court to kiss his hand and lean down to touch the clay, then said it could have been his last match at Roland-Garros.There also was the not-so-small achievement of claiming a gold medal for Serbia at the Paris Olympics less than a year ago by beating Alcaraz, no less. "These tournaments give me the biggest drive, still," Djokovic said. "I like the way I feel right now, physically. Tennis-wise, I've been playing good on the practice sessions. Obviously completely different when you start a tournament. I'll try to have a very good tournament and go as far as I can."

Club World Cup: Chelsea's late goals take down Benfica, 10-man Palmeiras beat Botafogo

The first two round of 16 matches in the Club World Cup went to extra time, with Chelsea taking the win over Benfica while Palmeiras edged past the in-form Botafogo despite having one player sent off.

NEW DELHI. Chelsea’s extra-time goals ensured they got the better of Benfica, while a 10-man Palmeiras dug deep to squeeze out a win over Botafogo in the first two round of 16 games at the FIFA Club World Cup on Sunday, 29 June.Chelsea’s clash against Benfica saw at least a two-hour delay due to a lightning storm in the Charlotte area, which triggered safety protocols and led to players and spectators being moved away from exposed areas.Once the game resumed, it was a fairly even contest until the second half, when a brilliant set-piece by captain Reece James gave Chelsea the lead. To make matters worse for Benfica,



Prestianni was sent off. However, the Portuguese side managed to equalise through a penalty converted by veteran Angel di Maria.Very proud. The performance, for me, was top until 85 minutes when they stopped the game and it started a completely different game," Chelsea manager Enzo Maresca commented."When you are inside for more than one hour, it's not easy. But 1-1, and then we continued to play, and the reward was the one that we deserved," he added. Once the match entered extra time, Chelsea completely outclassed their opponents, with Christopher Nkunku, Pedro Neto, and Kiernan Dewsbury-Hall all getting on the

scoresheet to seal their place in the next round.Meanwhile, in the battle between the Brazilian sides, Palmeiras came out on top with an extra-time winner to beat the in-form Botafogo 1–0. Paulinho scored the decisive goal in the 110th minute, although there was late drama as Gustavo Gmez was sent off in the 126th minute.“We played an incredible game,” Palmeiras manager Abel Ferreira told reporters.“We did very well in the 90 minutes and in extra time. We suffered together with one player less, but we deserved it,” he added.

The Brazilian sides have continued to impress in this competition and will be looking to go deep in the tournament, hoping to challenge the top European teams and prove they are also quality opposition.The next set of fixtures will see Lionel Messi’s Inter Miami take on PSG — a highly anticipated encounter, with the Argentine going up against his former club. It promises to be a contest to watch, especially as the reigning Champions League winners are set to be in action.

India pacer Khaleel Ahmed set to make county debut, signs deal with Essex

➡Khaleel Ahmed played for CSK in IPL 2025  
➡He picked 4 wickets vs England Lions  
➡He last played for India in 2024 in Sri Lanka

New Delhi. India seamer Khaleel Ahmed is all set to make his debut in County Cricket as he’s signed a deal with Essex. The left-arm seamer will be seen playing the remainder of the English County Championship and the entirety of the One-Day Cup.Ahmed recently had a good season with Chennai Super Kings (CSK) in the Indian Premier League 2025 (IPL 2025) as



he scalped 15 wickets in the tournament. The 27-year-old expressed excitement on his signing and is eyeing to make an immediate impact for the team.“I am thrilled to sign for Essex. I have heard a lot about the rich history of the Club, and I’m excited to be part of it and will look to make an immediate impact. I’m looking forward to playing at Chelmsford, meeting the loyal Essex Members and fans, and delivering performances they can be proud of,” Ahmed

told Essexcricket.Essex’s Director of Cricket, Chris Silverwood, was also delighted with Ahmed’s signing after his stellar performance against India A against the England Lions.

“We are really pleased to be bringing Khaleel into the Club. We were impressed with his performances for India A and firmly believe he can strengthen our already very strong seam attack. As a left-arm seamer, he offers something different and will add a new dynamic to the squad in both the One Day Cup and the County Championship,” Silverwood said.Ahmed scalped four wickets in the first innings of the second unofficial Test between India A and England Lions as he helped his team take a slender first innings lead. He will be expected to continue his good form for Essex, who are currently in eighth place in Division One of the County Championship with one win in eight games.



direction going into the semifinals. "It was an A-plus," the coach said. Vega's goal snapped a scoreless streak in international play that dates back to 2022. It also ended a dry spell for Mexico, which scored for the first time in 166 minutes of play. El Tri's final match in group play ended with a scoreless draw against Costa Rica. Mexico pushed ahead 2-0 in the 81st minute on an own goal by Saudi Arabia's Abdullah Madu. Mexico's Mateo Chavez sent a crossing pass to Roberto Alvarado, who never made contact with the ball. Instead, it caromed off a defending Madu and into the net. Saudi Arabia stifled Mexico's offense for much of a scoreless, physical first half. The tension escalated just before the halftime break — Saudi Arabia's Ali Majrashi and Mexico's Jesús Gallardo were both being shown yellow cards after the two exchanged shoves.

Let Shubman Gill captain for 3 years, even if we lose in England: Ravi

➡Former India head coach Ravi Shastri has urged the team management to retain Shubman Gill as the captain of the Test team for three years, irrespective of what happens in the ongoing series against England.

New Delhi. Former India head coach Ravi Shastri has urged the team management to retain Shubman Gill as captain, even if India lose the ongoing series against England. Gill has been appointed as India’s new skipper following the retirement of Rohit Sharma from the longest format of the game.The 25-year-old began his tenure in style as he became the fifth India captain to score a century on captaincy debut. However, his innings ended in vain as England beat India by five wickets as they chased down the target of 371 in the fourth innings.Despite India’s loss, Gill earned praise from Ravi Shastri, who extolled him for his maturity and urged the team management to let him continue as captain for three years.“He’s matured a lot. The way he handles the media, the way he talks at press conferences, at tosses—he’s matured a lot. Let him be there for three years. Don’t



chop and change irrespective of what happens in the series. Stick with him for three years, and I think he will deliver for you,” Shastri told Wisden. Furthermore, he also mentioned that the youngster has all the ingredients to be one of

the greats of the game and needs to adapt to the conditions with time. “I’ll be disappointed if Gill doesn’t go places. Languid, lazy elegance, and he’s got a regal element of being regal out there when he’s batting. If he can learn with exposure and adapt to conditions, I think that’s the one name I can see,” he added.Meanwhile, following India’s loss, several experts have been after Gill for his on-field tactics during the match. Hence, he has a major task at hand to regroup his men and prepare them for the second Test, set to begin from July 2 at Edgbaston, Birmingham.India have never won a Test match at the venue, having lost seven out of eight matches played. The Shubman Gill-led side will be up against history as they aim to level the series in the upcoming encounter.





# Rashami Desai

## BACKS Parag Tyagi As He Takes His Dog For A Walk: 'Her Sudden Passing...'

Rashami Desai was in the same season as late Shefali Jariwala in Bigg Boss 13. After expressing grief over Shefali's death on social media, she defended Parag Tyagi and criticised social media users for 'judging him' for walking their dog while holding his late wife's photo in one hand. She urged everyone to show empathy and not spread "sensationalism". Rashami posted a screenshot of Parag walking their dog Simba, whom Shefali was extremely close to. Taking to her Instagram story, she wrote, "Arreee bhaiya, let's spread kindness and compassion instead of judgment! Simba was more than just a pet – he was Shefali's beloved son. Her sudden passing leaves a huge void, and I urge the media to respect the family's grief and give them space during this difficult time. Let's show empathy and understanding, not sensationalism (sic)." Take a look:

Earlier today, Rashami shared a picture of Shefali and wrote, "I am still trying to process the news, you were an incredible person and I am struggling to find the words to express... You will be deeply missed, gone too soon." Meanwhile, Himanshi Khurana shared a throwback selfie with Shefali, and wrote, "Bigg Boss that place is cursed I think" along with heartbreak emoji.

**What did Shefali's residential security say?**

Shatrughan, the watchman of Shefali Jariwala's residential society, recounted the events that unfolded on the night of her death. He shared that Shefali was taken to the hospital around 10:30 PM on Friday. Still in shock, he remembered seeing Shefali and her husband Parag Tyagi just the evening before, casually walking their dog in the compound. "It was just like any other day," he said, adding, "I couldn't believe it when I heard on Friday night that she had passed away."

Shatrughan, the security guard on duty, recounted the events of Friday night. While speaking with , he mentioned, "Around 10:30 at night, Shefali ji was taken to the hospital. Before that, at around 9 PM, her husband Parag Tyagi came to the society on a motorcycle. I was the one who opened the gate." Shortly after Shefali was taken to the hospital, police teams and forensic units arrived at the scene, said Shatrughan. "The police have been inside since last night. There were two mobile forensic unit vehicles – one has left, one is still here," he added.

As for the latest update, police officials and forensic experts are still probing the case of her death. Her body was sent to Cooper Hospital for postmortem on Friday night.



## Sonakshi Sinha Pregnant? Actress Finally Breaks Silence, Says, 'I Have Found a Way...'



Sonakshi Sinha's personal life has often been under the media microscope — from whispers about her relationship with Zaheer Iqbal to public curiosity around her inter-faith wedding and now pregnancy rumours. The Heeramandi star, who tied the knot with longtime boyfriend Zaheer in a quiet civil ceremony last year, recently celebrated their first wedding anniversary on June 23, 2025.

The couple, who appeared together in Double XL (2022), kept their relationship under wraps for several years before making it official. But even after going public, the scrutiny didn't stop. Their interfaith relationship, with Sonakshi being Hindu and Zaheer Muslim, sparked even more curiosity. Many even questioned, "Is Sonakshi Sinha pregnant?" as she quietly got married without much fanfare.

Sonakshi, however, has chosen calm over chaos. In a recent interview, she reacted to the relentless noise surrounding her private life. "I have found a way of shutting out the noise," she said. "I live a very happy life off screen when I am not at work, and I am okay and peaceful, so when I am at work and I have to deal with such things, I just end up dealing with it better," the actress added.

The actress, who dated Zaheer Iqbal for seven years before they got married, shared how time and experience have helped her build emotional resilience. "You realise that people will say what they want to say, no matter what you do. If I say I am wearing white, someone will say no, it's black. Someone will always be there to challenge what you say, so you just move on with your life. You cannot pay attention to every little thing."

**Sonakshi Sinha and Zaheer Iqbal Marriage**

Sonakshi Sinha and Zaheer Iqbal got married in a quiet civil ceremony at her Bandra home on June 23, 2024. The wedding was attended by close family and a few friends, including her parents, Shatrughan and Poonam Sinha. Later that evening, the couple hosted a grand reception at Bastian restaurant in Mumbai.

The celebration was a star-studded affair with guests like Salman Khan, Rekha, Kajol, Anil Kapoor, Tabu, Raveena Tandon, Vidya Balan with Siddharth Roy Kapur, and many more.

## Shweta Tiwari's Ex-Husband Says He Gave Up Meeting Daughter Palak Tiwari: 'Beti Bhi Na Mil, Tu Bhi Na Mil'



Television actress Shweta Tiwari's ex-husband Raja Chaudhary is once again in the spotlight, shedding light on his past with her. Speaking in a candid interview, he shared details about their whirlwind romance, the family resistance they faced, and how their relationship deteriorated over time—allegedly after Shweta's rising success on TV. They crossed paths during a shoot and quickly grew close. "We dated only for 2-3 months, then we got married. She said that she was 19 but I always felt she was older, maybe 20-21. I was also 24-25 years old at the time. We got married in a rush. And then, shortly afterwards, our daughter was born. And soon after our daughter was born, she started getting those Ekta Kapoor serials," he said, in a chat with Hindi Rush.

While their relationship began with love, it didn't take long for differences to surface. Raja admitted that the cracks were visible quite early, even though they officially separated several years later. "We broke up some 6-7 years later and all this while, she would be on set and I would be at home, taking care of the daughter and taking care of the house," he said and added, "Awara dost bhi bana raha hu, usme kya hai? Gharwale kehte hain jo log sharab peete hain woh log awara hote hain. Toh kuch aise sharabi log maine dost bana liye," he said.

Their marriage had opposition from both sides, but they went ahead with it regardless. Raja shared how both families warned them against rushing things. "My family said, 'wait, let us see what's up' but I didn't listen to them. I said I will get married the next day. It was a mutual decision. Even her family members said, 'don't get married' but she snuck out of the house with her brother and came to the court to get married," he said. Shweta eventually became a well-known face in every Indian household after landing the lead role in Kasautii Zindagii Kay. According to Raja, this shift brought more tension into their personal life. "Life changed after her show became a huge hit. Then she started charging money by the hour."



# Falaq Naaz

## Takes Dig At Khushi Mukherjee's Revealing Dress?; Asks Govt 'Why No Penalty'

Television actress Khushi Mukherjee has been the talk of the internet recently, and not for her acting projects. The former Splitsvilla contestant and social media personality has found herself in the spotlight for her bold fashion choices, frequently making appearances in extremely revealing outfits that have gone viral across platforms.

While the internet remains divided over her clothing, actress Falaq Naaz—known for her role in Sasural Simar Ka—has now weighed in on the matter, without naming Khushi directly. In a strongly-worded Instagram video, Falaq referred to Khushi only as "didi" and expressed her frustration with the government's double standards when it comes to public decency and civic penalties. "Hi everyone," Falaq begins in the video. "Toh pichle baar aap sabko yaad hoga maine ek didi ke upar video banayi thi. Yaha pe na baat bahot zyada didi se aage jaa chuki hai. It is not about any XYZ person. It is something jo main government se puchna chahti hoon—ke stray dogs ke upar itna udham mach jata hai, penalties, hum log khaana nahi khila sakte, log objection lete hai."

The actress then draws a direct comparison between penalties for feeding stray animals and the lack of regulation over provocative public attire. "Iss tarah ka kuch pehenke agar sadak par nikal rahe hai toh uspe objection kyu nahi utha rahi hai government? Media jo inko cover

kar rahe hai, aur aise logon pe jo cover ho rahe hai, aise logon pe penalty kyu nahi hai? Mujhe yeh janna hai."

Falaq also made an emotional appeal to the public to raise this question with the authorities. "So, jitne log yaha pe baithe hue hai, help me out, tag authorities, and I want the answer now ke yeh sahi hai. Aur agar yeh sahi hai toh stray dogs ko



khaana khilane pe koi aawaz naa uthaaye. Agar nang pane mein aawaz nahi uthrahi, toh bachcho ko khaane khilane mein aawaz naa uthana."

Khushi Mukherjee, on the other hand, remains unfazed as paparazzi videos of her continue to rack up views. While she has yet to respond directly to Falaq's comments, her wardrobe choices have certainly kept social media buzzing—and now, they've sparked a wider debate around societal norms, personal freedom, and public decency.